राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 339, पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार , 18 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

टेस्ट चैंपियन बनने उतरेंगी भारत व न्यूजीलैंड की टीमें

साउथम्पटन, (एजेंसी)। भारत और न्यूजीलैंड शुक्रवार से यहां पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टेस्ट क्रिकेट का बादशाह बनाने के इरादे से उतरेंगे। इसके साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दो साल के क्रम का अंत हो जाएगा, जिसे टेस्ट क्रिकेट को नया जीवन देने के उद्देश्य के साथ 2019 में शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद चाहती है कि चैंपियनशिप से टेस्ट क्रिकेट को संदर्भ और मायने मिले और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन का मानना है कि यह सफल रहा है। प्रतियोगिता के अंतिम दौर में हमने देखा था कि टीमें क्वालीफाई करने पूरा जोर लगा रही थीं, इससे रोमांचक परिणाम देखने को मिले।

आरसी समेत दस्तावेजों को रिन्यू कराने की तिथि बढ़ी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), फिटनेस प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) और सभी प्रकार के परमिट की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है, जिनकी वैधता फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई थी। सरकार के इस फैसले से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी, जो कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से अपने दस्तावेजों को रिन्यू (नवीनीकृत) नहीं करा पाए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक एडवायजरी जारी कर इस संबंध में परिवहन विभागों को निर्देश दिया है।

बाबा रामदेव के खिलाफ एक और केस दर्ज

रायपुर, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना के इलाज में दी जा रहीं एलोपैथिक दवाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में उन पर यह केस दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाबा रामदेव के खिलाफ बुधवार रात को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ यूनिट ने एफआईआर कराई है। रायपुर के एसएसपी अजय यादव ने बताया कि रामदेव के खिलाफ केस फाइल किया गया है। महामारी को लेकर लापरवाही बरतने, अशांति फैलाने के इरादे से अपमान करने जैसे आरोपों के तहत उनके खिलाफ केस फाइल हुआ है।

इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 18 जुलाई को

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी ईएसई प्रीलिम्स यानी इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए बहु प्रतीक्षित टाइम - टेबल जारी कर दिया है। इस बार इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 18 जुलाई, 2021 को आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर टाइम - टेबल देख सकते हैं। समय सारणी के अनुसार, इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 02 से शाम 05 बजे तक होगी।

अक्षय कुमार ने स्कूल के लिए दिए एक करोड़ रुपए

जम्मू, (एजेंसी)। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार कश्मीर पहुंचे हैं। अक्षय कुमार गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास सुदूर तुलैल पहुंचे। इस दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ ही बीएसएफ के अधिकारी व जवान भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि अभिनेता दोपहर करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से तुलैल के नीरू गांव पहुंचे। उनका नीरू गांव में सेना और बीएसएफ जवानों के साथ बातचीत की। अक्षय कुमार ने नीरू गांव में स्कूल भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने नीरू गांव में सेना और बीएसएफ के जवानों से बातचीत की।

सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया 12वीं के छात्रों को अंक देने का फॉर्मूला

तीन साल के औसत पर मिलेंगे अंक, 31 जुलाई तक घोषित होगा रिजल्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की सीनियर सेकेंड्री और सीआईसीएसई की आईएससी बोर्ड परीक्षाओं की याचिका के दौरान एडवोकेट जनरल (एजी) के. के. वेणुगोपाल ने खण्डपीठ के समक्ष सीबीएसई 12वीं कक्षा के लिए ईवैल्यूएशन क्राइटेरिया प्रस्तुत किया। एजी ने खण्डपीठ को बताया कि 12वीं के मूल्यांकन के लिए स्टूडेंट्स के कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 इंटर्नल एग्जाम और प्रैक्टिकल के अंक जोड़े जाएंगे। इसमें से 10वीं और 11वीं के अंकों को 30 - 30 फीसदी वेटेज दिया जाएगा और 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड-टर्म और प्री-बोर्ड को 40 फीसदी वेटज दिया जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सीबीएसई द्वारा निर्धारित ईवैल्यूएशन क्राइटेरिया में पिछली कक्षाओं के बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ही मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा।

इसके साथ ही, एजी ने खण्डपीठ को बताया कि सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट 31 जुलाई 2021 तक घोषित कर दिया जाएगा। सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 के इन नतीजों को आज, 17 जून 2021 को जारी ईवैल्यूएशन क्राइटेरिया के आधार पर ही तैयारी किया जाएगा। जिसमें पिछली और वर्तमान कक्षाओं के इंटर्नल एसेसमेंट्स के अंक शामिल होंगे। गौरतलब है कि सीबीएसई ने पहले ही स्कूलों को 28 जून तक

लंबित इंटर्नल एग्जाम और प्रैक्टिकल को आयोजित करते हुए मार्क्स को सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये थे।

सीआईएससीई 12वीं को लेकर अगली सुनवाई 21 जून को

दूसरी तरफ, सीआईएससीई के अधिवक्ता द्वारा आईएससी के ईवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई से थोड़ा अलग स्कीम प्रस्तुत किया गया। सीआईएससीई की तरफ से कहा गया कि हम 3 की बजाय 6 कक्षाओं को आधार बनाने पर विचार कर रहे हैं और मूल्यांकन क्राइटेरिया सीबीएसई के लगभग समान ही होगा। हालांकि, खण्डपीठ से सीआईएससीई के अधिवक्ता द्वारा कुछ और समय की मांग की गयी। इसके बाद मामले की सुनवाई सोमवार, 21 जून 2021 तक के लिए टाल दी गयी।

सुबह 11 बजे हुई सुनवाई

निर्धारित समय के अनुसार सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीएसई की सीनियर सेकेंड्री और सीआईसीएसई की आईएससी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्रीय बोर्ड अपनी कक्षा 12 की रद्द परीक्षाओं के लिए 'ईवैल्यूएशन क्राइटेरिया' सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया। गौरलतब है कि सीबीएसई की सीनियर सेकेंड्री और सीआईएससीई की आईएससी की बोर्ड परीक्षाओं को महामारी के चलते रद्द कर दिया गया था।

पिछली सुनवाई 3 जून को हुई थी

उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खण्डपीठ द्वारा दोनो ही केंद्रीय बोर्डों की कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द करने और इंटर्नल एसेसमेंट के आधार पर जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने की वाली एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा दायर इस जन हित याचिका पर पिछल सुनवाई 3 जून 2021 को हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत द्वारा सीबीएसई को सीनियर सेकेंड्री और सीआईएससीई को आईएससी की रद्द परीक्षाओं के बाद स्टूडेंट्स के मूल्यांकन के लिए 'ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया' दो सप्ताह में बनाने को कहा था। वहीं, इससे पहले 31 मई 2021 को सीबीएसई और सीआईएससी की परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाले इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसके दौरान केंद्र सरकार और सीबीएसई का पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल (एजी) ने खण्डपीठ से अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए दो दिन का समय मांगा था। हालांकि, अगली सुनवाई के पहले ही सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद खण्डपीठ ने रिजल्ट तैयार करने के लिए सीबीएसई ईवैल्यूएशन क्राइटेरिया 2021 दो सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा था।

लिखित परीक्षा का भी मिलेगा मौका- वेणुगोपाल ने कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें स्थितियां सामान्य होने के बाद फिजिकल तरीके से परीक्षा देने का भी अवसर दिया जाए। अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए परीक्षा देना चाहेगा तो वह ऐसा कर सकेगा। इस पर जजों ने कहा कि यह सुझाव सही है, लेकिन अभी जिस तरीके से रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं, उस प्रक्रिया में भी इस बात को शामिल किया जाना चाहिए कि रिजल्ट से शिकायत होने पर छात्र दोबारा मूल्यांकन की मांग कर सकें। केंद्र के वकील ने इससे सहमति जताते हुए कहा कि इसकी भी व्यवस्था बनाई जाएगी। आईसीएसई की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील जेके दास ने कोर्ट को बताया कि उनके बोर्ड ने 6 साल के एस्ट के आधार पर रिजल्ट तैयार करने का फैसला लिया है। उनके रिजल्ट भी 31 जुलाई तक आ जाएंगे जजों ने इसे नोट कर लिया।

भारत शांति का 'पुजारी' है लेकिन आक्रामकता का जवाब देने में सक्षम है : राजनाथ

किमीन (अरुणाचल प्रदेश)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत वैश्विक शांति का ''पुजारी'' है, लेकिन यह आक्रामक कार्रवाईयों का करारा जवाब देने में सक्षम है. इस दौरान उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमा के पास निर्मित 12 सड़कों का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज बीआरओ द्वारा निर्मित 12 रोड परियोजनाओं को एक साथ राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक नॉर्थ-ईस्ट का विकास नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से पूर्वोत्तर का विकास हुआ है उसकी जितनी भी सराहना की जाए काम है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि इस इलाक़े का सामरिक महत्व है। कई देशों के साथ इस इलाक़े की सीमाएं लगती हैं। विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन सड़कों से इस इलाक़ों में रहने वाले लोगों को बहुत लाभ होगा। यह हमारी सरकार के एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के अंतर्गत उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं, जिसके तहत सरकार सीमाई क्षेत्रों के संपूर्ण विकास पर बहुत अधिक जोर दे रही है। सीमावर्ती राज्यों में बड़ी संख्या में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों के कार्य को पूरा किया गया है।

राजनाथ ने आगे कहा कि पिछले सात सालों के दौरान सड़क परियोजनाओं और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बीआरओ के बजट में तीन से चार गुना की वृद्धि की गई है। पिछले सात सालों में यहाँ की सुरक्षा की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। विद्रोह से सम्बंधित घटनाओं में 85 फ़ीसदी, और नागरिकों और सुरक्षा बलों की कैजुएलटी में काफ़ी कमी आयी है।

राजनाथ ने आगे कहा कि आज इस प्रदेश के किसानों की पहुंच देश ही नहीं, विदेशों तक बढ़ी है। आप लोगों को शायद मालूम होगा,कि यहाँ से थोड़ी दूर पर, सुबनसिरी इलाके में एक फल होता है, जिसे अंतेरी कहा जाता है। लोग थोड़ा-बहुत उसे खुद खाते थे, बाकी पशुओं को डाल देते थे। दो दिन पहले ही गलवन घाटी में हुई घटना को एक साल बीते हैं। भारतीय सेना ने अपने शौर्य का पराक्रम का परिचय देते हुए अपना बलिदान दिया है।

सरकार की आलोचना करें, लेकिन संविधान मानना होगा रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तकरार को लेकर गुरुवार को टीवी9 भारतवर्ष को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर को भारत का कानून मानना होगा. उन्होंने कहा कि भारत में ट्विटर के दोहरे मानक नहीं चलेंगे. ट्विटर सरकार की आलोचना करे, लेकिन देश का संविधान मानना होगा. कानून मंत्री ने कहा कि ट्विटर को सरकार ने कई मौके दिए उसे तीन महीने का समय भी दिया गया था. सरकार ने 25 फरवरी को गाइडलाइंस जारी की गई थी.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो नाम नहीं लेंगे, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता ट्विटर से ही राजनीति कर रहे हैं. साथ ही कहा कि आजकल वो ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा, कैपिटल हिल्स के लिए अलग नीति और लाल किला के लिए अलग नीति नहीं चलेगी. 3-4 साल से ट्विटर की गतिविधियों पर नजर थी. कानून के पालन के लिए ही गाइडलाइंस बनाई गई हैं. उन्होंने साथ ही कहा कि ट्विटर पर अचानक से कार्रवाई नहीं की गई. ट्विटर की तरफ से कोर्ट में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो देखा जाएगा.

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ऑफिस अमेरिका में और पैसा भारत में कमाएंगे. भारत की कंपनियां भी दूसरे देशों में हैं और वो भी उन देशों के कानूनों को मानती हैं. कानून मंत्री ने साफ किया कि ये लड़ाई सरकार बनाम ट्विटर या फिर बीजपी बनाम ट्विटर की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई ट्विटर बनाम ट्विटर के यूजर के बीच की है.

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर तूफान से भारी नुकसान

इंडिगो सहित कई कंपनियों के विमान क्षतिग्रस्त

अहमदाबाद, (एजेंसी)। अचानक आए तूफान के कारण अहमदाबाद हवाई अड्डे पर विमानन कंपनी इंडिगो और गो फर्स्ट के कुल पांच विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विमानन उद्योग के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक बुधवार शाम आए तूफान के कारण इंडिगो के तीन विमान, जिनकी पंजीकरण संख्या वीटी-आईवीओ, वीटी-आईटीडी और वीटी-आईवीक्यू है, क्षतिग्रस्त हुए हैं। गो फर्स्ट के दो विमान जिनकी पंजीकरण संख्या वीटी-डब्ल्यूजीवी और वीटी-डब्ल्यूजेजी है, भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इंडिगो ने इस मामले पर एक बयान में कहा कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर बुधवार की शाम अत्यधिक तेज हवाओं के साथ एक अप्रत्याशित तूफान आया। इसके कारण हवाई अड्डे पर खड़े हुए कंपनी के विमानों के अलावा कई एयरलाइंस के विमान क्षतिग्रस्त हुए।

इंडिगो ने कहा कि क्षतिग्रस्त हुए विमानों के कुछ हिस्सों को बदला जाएगा। आवश्यक मरम्मत कार्य के बाद विमान परिचालन में लाए जाएंगे। गो फर्स्ट ने इस मामले को लेकर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

राष्ट्रपति और धनखड़ के बीच दो घंटे चली बातचीत

शाम को गृहमंत्री शाह से की मुलाकात, राज्यपाल के दिल्ली दौरे पर सियासत तेज

नई दिल्ली ■ एजेंसी

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा और अंदरूनी कलह से जूझ रही प्रदेश भाजपा के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली दौरे पर हैं। इसी कड़ी में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत की। शाम को वह गृह मंत्री अमित शाह से मिले।

गवर्नर हाउस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि जगदीप धनखड़ चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर लगातार बंगाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं ममता सरकार उनके दावों को लगातार खारिज कर रही है।

नंदीग्राम चुनाव परिणाम पर ममता ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

कोलकाता, (एजेंसी)। नंदीग्राम चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। नंदीग्राम सीट से सीएम ममता बनर्जी को भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में 110764 वोट मिले थे, जबकि ममता बनर्जी को 108808 वोट मिले।

बुजुर्ग की पिटाई का मामला

स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ शिकायत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की बुरी तरह से पिटाई के बाद उसकी दाढ़ी काटने के मामले में वायरल वीडियो का मुद्दा गरमाता ही जा रहा है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस को स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी एवं अन्य के खिलाफ तिलक नगर पुलिस थाने में शिकायत मिली है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

72 साल के बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है। उन्होंने लोनी बार्डर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई को कहा है। विधायक ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि बीते पांच जून को लोनी में साजिश के तहत 72 साल के एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई, मारपीट की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपने आधिकारिक वेरिफाई ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के लखीमपुर जिले में किमिन-पोटिन रोड के उद्घाटन के दौरान।

सोनिया गांधी ने लगवाया टीका, बेवजह के मुद्दों के बजाय टीकाकरण के 'राजधर्म' का पालन करे सरकार: रणदीप सुरजेवाला

नई दिल्ली कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें ले चुकी हैं और सरकार को बेवजह के मुद्दे गढ़ने की बजाय सभी भारतीय नागरिकों का टीकाकरण कराने के 'राजधर्म' का पालन करना चाहिए. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने टीके की पहली खुराक ले ली है और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोविड से पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद चिकित्सकों की सलाह पर टीका लगवाएंगे.

उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की है, जब भाजपा कई नेताओं की तरफ से सवाल किया गया कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने टीके लगवाए हैं. सुरजेवाला ने बताया, ''फिजूल के मुद्दे गढ़ने की बजाय मोदी सरकार को रोजाना 80 लाख से एक करोड़ भारतीय नागरिकों को टीका लगवाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि 31 दिसंबर, 2021 तक 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य पूरा हो सके.''

उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''कोरोना वायरस की दूसरी लहर में भारत के लोगों को निराश करने के बाद इस सरकार का यही राजधर्म बनता है कि वह सभी लोगों का टीकाकरण करवाए.'' कांग्रेस महासचिव ने कहा, ''हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्हें यह जानना चाहिए कि कांग्रेस अध्यक्ष कोविशील्ड की दो खुराकें ले चुकी हैं.''

उन्होंने बताया, ''राहुल गांधी को 16 अप्रैल, 2021 को टीका लगवाना था. हल्के फ्लू के लक्षण दिखने के बाद उनकी जांच हुई और फिर 18 अप्रैल को उनके कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई. पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद और चिकित्सकों के परामर्श के मुताबिक वह टीका लगवाएंगे.'' सुरजेवाला ने यह जानकारी भी दी कि प्रियंका गांधी ने टीके की पहली खुराक ले ली है.

उन्होंने कहा, ''इसके बाद 28 मार्च को उनके पति (रॉबर्ट वाड्रा) कोरोना से संक्रमित हो गए और वह भी संपर्क में आई थीं. वह और उनके पति टीकाकरण के लिए जरूरी अनिवार्य अवधि बीतने के बाद अब टीका लगवाएंगे.'' सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री देश में कोरोना के व्यापक कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं.

सुरजेवाला ने कहा, ''टीकाकरण को लेकर पिछले छह महीनों में स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के 'व्यापक कुप्रबंधन' के कारण सिर्फ 3.51 फीसदी आबादी का टीकाकरण हो पाया है. पिछले छह महीनों के दौरान रोजाना औसतन 17.23 लाख लोगों को टीका लगा.'' उन्होंने दावा किया, ''इस गति से देश के 94.50 करोड़ वयस्क लोगों को टीका लगाने में 944 दिन और लगेंगे. इसका मतलब यह टीकाकरण 16 जनवरी, 2024 तक चलेगा.''

पालघर के डहाणू में पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू में एक पटाखा फैक्टरी में विस्फोट होने से भीषण आग लगी है। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। फायर वर्क्स नाम की पटाखा फैक्टरी डहाणू हाईवे से करीब 15 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है। विस्फोट के बाद लगी आग से 10 से 15 किमी तक के घरों में नुकसान होने की खबर है। इस फैक्टरी में गुरुवार सुबह 9 बजे भीषण विस्फोट हुआ। उसके बाद आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया।

10-15 किलोमीटर तक घरों को पहुंचा नुकसान

डहाणू कलेक्टर के मुताबिक, आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। हालांकि, ये विस्फोट कैसे हुआ और आग कैसी लगी इसकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा, देवांगना और आसिफ को मंगलवार को दी थी जमानत

तीनों एक्टिविस्ट को किया तिहाड़ जेल से रिहा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली दंगा मामले में छात्र कार्यकर्ता देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तनहा को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। इनको मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की थी।

इन छात्रों को पिछले साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े मामले में मई 2020 में गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहा नहीं करने पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसके संबंध में उनके वकील ने निचली अदालत में शिकायत की थी कि कई घंटे बीतने के बाद भी जेल से रिहा नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। जज ने पते और जमानतदारों के सत्यापन में देरी पर पुलिस को फटकारते हुए कहा कि मैं कहूंगी कि यह उचित कारण नहीं हो सकता है कि जब रिपोर्ट दाखिल नहीं हो जाती, तब तक आरोपी को जेल में रखा जाए।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पुलिस ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने सबूतों की बजाय सोशल मीडिया में लिखी जा रही बातों से ज्यादा प्रभावित होकर फैसला दिया है।

संक्षिप्त समाचार

नासा के रोवर परसिवरेंस ने मार्स पर देखी धरती पर मौजूद वॉल्केनिक रॉक जैसी चट्टान

वाशिंगटन । अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने बताया है कि मार्स पर गए उसके रोवर परसिवरेंस को वहां पर धरती पर मौजूद चट्टान की तरह ही एक चट्टान मिली है। नासा परसिवरेंस मार्स रोवर के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जारी ट्वीट में कहा गया है रोवर इस बड़े से पत्थर के पास से गुजरा था। इस चट्टान में धरती पर पाई जाने वाली चट्टानों जैसे काफी कुछ समानता थी। ये धरती पर मौजूद ज्वालामुखी चट्टानों की तरह ही है। इसमें रोवर की तरफ की तरफ से कहा गया है कि वो यहां पर ऐसी चट्टानों को खोजने में जुटा है जिसमें अलग-अलग परत मौजूद हों और जिसमें जीवन के कुछ सुबूत मिल सकते हों। कुछ दिन पहले किए गए एक ट्वीट में रोवर ने अपने उस रूट की मैपिंग की जानकारी दी थी जिसके दायरे में रहकर वो जीवन के सुबूत तलाशने में जुटा है। इसमें बताया गया था कि वो पहले दक्षिण में फिर उत्तर में यहां पर मौजूद डेल्टा के पास कुछ शोध करेगा, जहां माना जाता है कि कभी कोई नदी थी। आपको बता दें कि नासा का परसिवरेंस रोवर लाल ग्रह के जेजीरो क्रेटर में 18 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक उतरा था। इस जगह का चयन पांच साल के अथक प्रयासों के बाद किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां पर कभी एक झील हुआ करती थी जो अब सूख चुकी है। वैज्ञानिकों को ये भी उम्मीद है कि यहां पर सूक्ष्म रूप में जीवन हो सकता है। ये क्रेटर करीब 45 किमी चौड़ा है। वैज्ञानिकों को यहां से कुछ ऐसे खनिजों की मौजूदगी का पता लगा है जो इसकी पुष्टि करते हैं। जिस जगह पर परसिवरेंस उतरा है वो जगह क्यूरोसिटी की लैंडिंग साइट से करीब 3700 किमी दूर है। आपको यहां पर ये भी बता दें कि नासा का ये 9वां रोवर है जो मार्स पर सफलतापूर्वक उतरा है। इससे पहले नासा फोनेक्स, विकिंग-1, विकिंग-2, पाथफाइंडर, ऑपर्च्युनिटी, इनसाइट, क्यूरोसिटी, स्पिट को भी लाल ग्रह पर उतार चुका है। गौरतलब है कि नासा के परसिवरेंस के साथ एक 2 किग्रा वजनी हेलीकॉप्टर भी मार्स पर भेजा गया था। इस ग्रह पर इसकी पहली उड़ान 19 अप्रैल 2021 को हुई थी। इससे पहले इसको चार पर विभिन्न कारणों से रोकना पड़ा था। इस उड़ान से ये साबित हो गया है कि नासा के वातावरण में उड़ान भरना संभव है। ये मार्स के भावी मिशन के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ है। अपनी पहली उड़ान के दौरान ये करीब 10 फीट की ऊंचाई तक गया था। धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर और पहला सफल मिशन भी है।

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद लोगों को शहर छोड़ने की मिली अनुमति

सिडनी । ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर ने कोरोना वायरस के भयंकर प्रकोप के बावजूद लोगों को शहर छोड़ने की अनुमति दे दी है। कोरोना प्रकोप के खिलाफ लड़ाई के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अपने 50 लाख निवासियों को घर से 25 किलोमीटर (15 मील) से अधिक की यात्रा करने की अनुमति देगा और बाहर पहनने वाले अनिवार्य मास्क को समाप्त कर देगा। मेलबर्न पिछले सप्ताह के अंत में दो सप्ताह के कठिन लॉकडाउन से बाहर आया है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ये इसका चौथा प्रकोप था। जहां 24 मई से लगभग 100 मामले देखे गए हैं। विक्टोरिया राज्य के कार्यवाहक प्रीमियर जेम्स मर्लिनो ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि विक्टोरिया अपने सबसे अच्छे समय में होता है जब हम सब एक साथ होते हैं। राज्य कल रात से एक साथ वापस आ जाएगा। हालांकि एक आवासीय टाउनहाउस परिसर में एक ताजा क्लस्टर से जुड़े मामले बुधवार को थोड़े बढ़े, मेलबर्न धीरे-धीरे प्रतिबंधों में ढील देगा।

सार्वजनिक समारोहों में लोगों की संख्या को बढ़ाकर 20 लोगों तक किया जाएगा, जबकि घरेलू समारोहों पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। मेलबर्न में जिम खुल सकते हैं, लेकिन उन्हें सख्त नियमों का पालन करना चाहिए और सैलून सेवाएं सेवा के दौरान बिना मास्क के चल सकती हैं। विक्टोरिया ने बुधवार को पांच नए स्थानीय मामले दर्ज किए, जो सभी टाउनहाउस क्लस्टर से जुड़े थे, जिससे वहां कुल संक्रमण आठ हो गए। बुधवार के आंकड़ों में मंगलवार को घोषित दो मामले शामिल हैं जो मध्यरात्रि कट-ऑफ की समय सीमा के बाद दर्ज किए गए थे। अधिकारियों ने माना कि नए मामले सामुदायिक प्रसार के कम जोखिम वाले हैं क्योंकि सभी मौजूदा प्रकोप से जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी। स्विफ्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, स्नैप लॉकडाउन और सख्त सामाजिक दूर करने के उपायों ने ऑस्ट्रेलिया को प्रकोपों को पहले के प्रकोपों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में मदद की है और केवल 30,300 मामलों और 110 मौतों के साथ अपने कोरोना संख्या को अपेक्षाकृत कम रखा है।

कुलभूषण जाधव मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाली, भारतीय उच्चायोग के वकील को पेश होने को कहा

इस्लामाबाद । पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देश अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के अनुरोध पर मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने की सरकार की याचिका पर सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने भारतीय उच्चायोग के वकील को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश होने का नोटिस भी जारी किया। 7 मई को मामले की आखिरी सुनवाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने भारत को 15 जून तक जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया था। पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली से एक ऐसा विधेयक पारित कराया, जिसके तहत भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार दे दिया गया है। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन ने गत हफ्ते गुरुवार को आइसीजे (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) के आदेश के अनुसार जाधव को राजनयिक पहुंच देने की भी इजाजत दी गई है। सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच से इन्कार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आइसीजे का दरवाजा खटखटाया था। हेग स्थित आइसीजे ने जुलाई 2019 में फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा करनी चाहिए और बिना किसी देरी के राजनयिक पहुंच प्रदान करना चाहिए। आइसीजे ने अपने फैसले में पाकिस्तान से जाधव को दी गई सजा के खिलाफ अपील के लिए एक उचित मंच प्रदान करने को भी कहा था।

जापान में दिखा भूकंप-सुनामी का 'तांडव', 125 फीट ऊंची लहरों ने मचाई जबरदस्त तबाही, 26 हजार लोगों की हुई मौत

टोक्यो, एजेंसी । 'रिंग ऑफ फायर' के करीब स्थित होने की वजह से जापान को लगातार भूकंप और सुनामी की मार झेलनी पड़ती है. इस वजह से जापान में अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसी ही एक भूकंप और फिर सुनामी की आपदा आज ही के दिन 1896 में आई थी. जब 8.5 तीव्रता के भूकंप से अभी जापान उबर ही रहा था कि उसे भयानक सुनामी का सामना करना पड़ा. ये भूकंप जापान के उत्तरपूर्वी तट पर आया. इसके बाद भूकंप की वजह से भयानक सुनामी आई और इसने तटीय इलाके में भारी तबाही मचाई.

इस घटना में 26,000 लोग मारे गए. 15 जून 1896 को जापान के होंशू में स्थित सानरिकू तट पर 8.5 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप का केंद्र तट से 90 मील की दूरी पर था, जहां पर समुद्र की गहराई बहुत अधिक थी. इतनी अधिक तीव्रता का भूकंप होने के बाद भी तटीय इलाकों पर दूरी अधिक होने की वजह से इसका प्रभाव कम देखने को मिला. यही वजह थी कि लोगों को सुनामी का अंदेशा भी नहीं था. लेकिन भूकंप के झटके महसूस होने के 35 मिनट बाद एक भयानक सुनामी तट की ओर बढ़ी. इसकी लहरें बेहद ही खतरनाक थीं और पहली लहर के पांच मिनट बाद ही दूसरी विशालकाय लहर भी तट से आकर टकरा गई.

म्यांमार के लिए पिघला तानाशाह किम का दिल, 16 वर्ष में पहली बार यूएन के जरिए दी आर्थिक मदद

सिओल । पूरी दुनिया में अपने तानाशाही रवैये से पहचान बनाने वाले उत्तर कोरिया ने वर्ष 2005 के बाद से पहली बार यूएन के जरिए तख्ता पलट का शिकार हुए म्यांमार को 3 लाख डॉलर की मदद दी है। उत्तर कोरिया ने ये मदद मानवीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र को मुहैया करवाई है। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस ऑफ ह्यूमेनिटेरियन अफेयर्स (ओसीएचए) फाइनेंशियल ट्रेकिंग सर्विस का कहना है कि उत्तर कोरिया ने ये मदद 24 मई को म्यांमार ह्यूमेनिटेरियन फंड में जमा करवाई है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की मदद के लिए 276 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद का आह्वान किया था, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने ये कदम उठाया है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले डेढ़ लाख डॉलर की आर्थिक मदद इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, और श्रीलंका के लिए वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र को दी थी। उस वक्त ये सभी देश वर्ष 2004 में आई सुनामी की वजह से भयंकर रूप से पीड़ित थे। बता दें कि म्यांमार में 1 फरवरी को सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद से अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं जबकि हजारों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं। देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने वाले लोगों की भी संख्या हजारों में है। संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार म्यांमार में लोगों के भुखमरी का शिकार होने और मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा चुकी है।

इन कार्यकर्ताओं की अपील है कि म्यांमार में जल्द से जल्द अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मदद की और कार्रवाई की दरकार है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यहां पर हालात काफी खराब हो सकते हैं। म्यांमार में सेना द्वारा वहां की आंग सांग सू की के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के बाद से ही जनता और सेना आमने सामने है। सेना लगातार अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को बेदर्दी से कुचलने में लगी है। विरोध प्रदर्शनों के बीच पहले से आर्थिक मार झेलने वाले म्यांमार में कोरोना महामारी ने स्थिति और अधिक विकट कर दी है।

आपको यहां पर ये भी बताना जरूरी है कि उत्तर कोरिया के म्यांमार से काफी पुराने संबंध है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक उत्तर कोरिया इस दक्षिण पूर्वी देश को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। यूएन के मुताबिक इन दोनों देशों के बीच मिसाइल में सहयोग को लेकर भी जांच की जा रही है। म्यांमार के लिए दक्षिण कोरिया ने भी मानवीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र को 6 लाख डॉलर की मदद मुहैया करवाई है। हालांकि दक्षिण कोरिया ने म्यांमार को किसी तरह के रक्षात्मक सहयोग और हथियारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

ओलंपिक खेलों से पहले वायरस आपातकाल को कम करेगा जापान, घट रहे कोरोना के नए केस

टोक्यो । महीने भार बाद देश में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए जापान ने अंतिम तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत जापान सप्ताह के अंत तक टोक्यो समेत छह अन्य क्षेत्रों से कोरोना वायरस आपातकाल की स्थिति को कम करने के लिए घोषणा करेगा। जापाल ने लिए अच्छी बात ये है कि यहां कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले रोजाना कम हो रहा हैं। जापान मार्च के अंत से ही कोरोना संक्रामक की नई लहर को धीमा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। देश में नए दैनिक मामले एक समय पर 7,000 के पार पहुंच गए थे। टोक्यो, ओसाका और अन्य महानगरीय क्षेत्रों में अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार रोगियों की संख्या बढ़ गई थी। तब से दैनिक मामलों में काफी कमी आई है। नए मामलों में कमी को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार को समाप्त हो रहे आपातकाल में प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा कुछ ढ़ील दे सकते हैं।

ओलंपिक आयोजित करने के संभावित जोखिमों पर चिकित्सा विशेषज्ञों और जनता की चिंताओं के बावजूद प्रधानमंत्री सुगा ने कहा है कि वह 23 जुलाई से शुरू होने वाले सुरक्षित ओलंपिक खेलों को आयोजित करने के लिए दृढ़ हैं। हालांकि, गुरुवार को एक वायरस पैनल की बैठक में विशेषज्ञों ने टोक्यो, इइची, होक्काइदो, ओसाका, क्योटो, ह्योगो और फुकुओका में आपातकाल को कम करने की सरकारी योजनाओं को प्रारंभिक मंजूरी दी है।

बाढ़ के कहर से सात की मौत, तीन भारतीय और तीन चीनी नागरिकों समेत कई लापता

काठमांडू । नेपाल के सिंधुपालचौक जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ ने सात लोगों की जान ले ली है। वहीं, कई लोगों के लापता होने की खबर है। लापता होने वालों में भारतीय और चीनी नागरिक भी शामिल हैं। सिंधुपालचोक के जिला प्रशासन कार्यालय ने पुष्टि करते हुए कहा कि बाढ़ में अबतक 20 लोग लापता हुए हैं जिनमें तीन भारतीय और तीन चीनी नागरिक भी शामिल हैं। बारिश के कारण यहां नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। कल जिला प्रशासन ने आशंका जताई थी कि बाढ़ मेलमची और इंद्रावती नदी के मुख्य स्रोत से उत्पन्न हुई है।

बाढ़ के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों के घरों में पानी चला गया है, बिजली के खंभे टूटकर नीचे गिर गए हैं और इसके अलावा लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मेलमची में पानी और कीचड की मोटी लेयर बन गई है, जिस वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक, करीब 200 घर इस कारण आंशिक और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी के तीन सदस्यों समेत 7 सांसदों की एंट्री बैन

इस्लामाबाद । पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने सात सदस्यों को असंसदीय व्यवहार के चलते प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया है। प्रतिबंधित किए गए सांसदों में सत्ताधारी पार्टी तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के तीन सांसद भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अखबार द डॉन की खबर के मुताबिक असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने इन तीनों सांसदों को बजट पुस्तिका को फेंकने और अपशब्द कहे जाने की वजह से असेंबली में प्रवेश से प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा उन सांसदों को भी प्रतिबंधित किया गया है जिन्होंने संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ को असेंबली में बोलने के दौरान बाधा पहुंचाने या उन्हें परेशान करने की कोशिश। स्पीकर असद कैसर ने सांसदों के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी का इजहार करते हुए उनके व्यवहार को असंसदीय करार दिया। स्पीकर ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है।

स्पीकर ने असेंबली में शाहबाज शरीफ के भाषण में बाधा डालने वाले सांसदों की फोटो को भी शेयर किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि 14-15 जून को इन सांसदों द्वारा किया गया व्यवहार बेहद खराब था। उन्होंने एक आदेश में कहा कि जिन लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया है उनके नाम उजागर किए जाएं। इन्होंने लगातार चेतावनी देने के बाद भी संसद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई और नियमों की अवहेलना की।

पीटीआई के जिन सांसदों को असेंबली में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है उनके नाम फहीम खान, अब्दुल माजिद खान, अली नवाज अवान हैं। इसके अलावा पीएमएल-एन के अली गौहर खान, शेख रोहाले असगर और चौधरी हामिद हमीद, पीपीपी के सैयद आगा रफीउल्लाह शामिल हें। स्पीकर ने अपने आदेश में ये साफ किया है कि इन सभी को अगले आदेश तक असेंबली में नहीं घुसने देना है। स्पीकर ने विपक्षी पार्टी द्वारा असेंबली में सरकार के बजट प्रस्ताव के बीच पीएम इमरान खान पर किए गए हमले के बाद सदन की कार्रवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। बजट प्रस्ताव का विरोध करने वाले सांसदों का कहना था कि ये प्रस्ताव देश के लोगों को रोजगार देने और महंगाई दर को कम करने में मदद नहीं करता है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर कहासुनी हुई और दोनों ही तरफ से काफी शोरगुल भी हुआ। इतना ही नहीं सांसद इससे आगे बढ़कर आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के ऊपर बजट की कॉपी तक फेंकने लगे थे। इसके बाद स्पीकर ने इन सांसदों को प्रतिबंधित किया।

पीएमएल-एन के अध्यक्ष ने बोलना शुरू किया तो दूसरी तरफ से नारेबाजी की जाने लगी और उन्हें परेशान करने के लिए सीटियां बजाई जाने लगी। शाहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान नियाजी ने देश के एक करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था लेकिन वो नौकरियां कहां हैं। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि वो 300 बिलियन डॉलर कहां है जो सरकार ने विदेशों से वापस लाने की बात कही थी।

चीन ने अमेरिका में कोरोना टेस्टिंग पर उठाया सवाल, वहां के तमाम जैव हथियारों की जांच पर दिया जोर

शंघाई । अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी दुनिया में फैले महामारी कोविड-19 के लिए दोषी करार चीन अब अमेरिका पर यह आरोप लगाने की कोशिश में जुट गया है। चीन के महामारी विशेषज्ञों ने कहा है कि अमेरिका के आधिकारिक तौर पर संक्रमण के मामले की घोषणा से पहले ही वहां के सात राज्यों में करीब पांच लोग कोविड-19 के चपेट में आ चुके थे लेकिन वहां शुरुआत में कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया काफी धीमी थी।बता दें कि कई देशों के राजनीतिज्ञों ने चीन के लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की संभावना को लेकर जांच पर जोर दिया है।

चीन के मुख्य महामारी विशेषज्ञ जेंग गुआंग ने ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में बताया कि यह ध्यान अब अमेरिका की ओर जाना चाहिए जहां महामारी की शुरुआत में टेस्टिंग की प्रक्रिया काफी धीमी थी और वहां अनेक बायोलॉजिकल लैब हैं।

उन्होंने कहा, देश में मौजूद सभी जैव हथियारों की जांच की जानी चाहिए। बुधवार को अमेरिकी अध्ययन को निशाने पर लेते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि यह संभव है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत कई जगहों से हुई हो और अन्य देशों को भी इसमें डब्ल्यूएचओ का सहयोग करना चाहिए। महामारी की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका व चीन के बीच राजनीतिक तनाव शुरू हो गया। चीन के वरिष्ठ महामारी विशेषज्ञ ने कहा है कि कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के अगले चरण में अमेरिका को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने यूएन को पत्र लिखकर फिर अलापा कश्मीर का राग, 5 अगस्त 2019 का फैसला पलटने को कहा

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को एक पत्र लिखकर फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बताया कि इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजा गया है।

सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नियमित रूप से पत्र लिखने वाले कुरैशी ने अपने नवीनतम पत्र में आरोप लगाया है कि भारत फर्जी अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र जारी करके और अन्य उपायों से कश्मीर की जनसांख्यिकीय संरचना को बदल रहा है। उन्होंने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि वह भारत से पांच अगस्त, 2019 और उसके बाद के अपने कदमों को पलटने के लिए कहे। कुरैशी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ परिणामोन्मुखी संबंध के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है और पाकिस्तान भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है।

तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। बता दें कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया।

ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट से हड़कंप, संक्रमण के मामलों में 50फीसदी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होने का दावा

लंदन । ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट से हड़कंप मच गया है। एक अध्ययन के मुताबिक, ब्रिटेन में मई से कोरोना वायरस के मामलों में 50 फीसदी बढ़ोत्तरी के लिए डेल्टा वैरिएंट जिम्मेदार है। गुरुवार को इंपीरियल कॉलेज लंदन के नेतृत्व में एक बड़े प्रसार अध्ययन में पाया गया कि डेल्टा कोरोना वैरिएंट के तेजी से प्रसार ने मई से इंग्लैंड में संक्रमण में 50त्न की वृद्धि की है। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने मंगलवार को वायरस के डेल्टा स्वरूप के मामलों में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा भारत से यात्रियों के आने पर रोक के फैसले को देरी से लागू करने को जिम्मेदार ठहराया था। वायरस का यह स्वरूप सबसे पहले भारत में सामने आया था और मामलों में बढ़ोतरी की वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन को चार और हफ्तों के लिए 19 जुलाई तक बढ़ाना पड़ा है। अमेरिका में वैक्सीन लगाने का काम तेजी से चलने के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या छह लाख के पार हो गई है। यहां कोरोना के डेल्टा वैरिएंट को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हो गए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन ने चेतावनी दी है कि कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जनता जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाए। अमेरिका के सेंटर फार डिजीज एंड प्रीवेंशन सेंटर ने कोरोना के डेल्टा वैरिएंट को लेकर चिंता जताई है। यह वैरिएंट ज्यादा घातक और संक्रामक है। सीडीसी के अनुसार यह अल्फा वैरिएंट से पचास फीसद ज्यादा तेजी से फैलता है।

अफगानिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन अभियान के दौरान हिंसा, 5 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत; यूएन ने की निंदा

काबुल, एजेंसी । संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में जारी पोलियो टीकाकरण अभियान को निशाना बना स्वास्थ्यकर्मियों की हत्या के मामले की निंदा की है। अफगानिस्तान में मंगलवार को पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान पांच स्वास्थ्यकर्मियों की हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कोऑर्डिनेटर रमीजअलकबारोव ने घटना पर नाराजगी जाहिर की और कहा, इस तरह के संवेदनहीन हिंसा को रोकना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले में मारे गए स्वास्थ्यकर्मियों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

ड्ढ॥ह्र प्रमुख टेड्रोस अधनम घेब्रेसस ने ट्वीट कर इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि इस हमले से वे अंदर तक दुखी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा और टीकाकरण अभियान बिना किसी रुकावट के चलाई जानी चाहिए ताकि समुदायों को सुरक्षित रखा जा सके। बता दें कि यूनिसेफ के सहयोग से अफगानिस्तान सरकार देश के 96 लाख बच्चों को पोलियो के टीके की खुराक देना चाहती है। वर्ष 2020 में अफगानिस्तान में पोलियो के 54 नए मामले आए थे। आतंकियों के खतरे के मद्देनजर पोलियो टीकाकरण टीम को सुरक्षा भी मुहैया करायी जाती है। इसके बावजूद अफगानिस्तान और पड़ोस के पाकिस्तान में आए दिन पोलियो टीम को निशाना बनाया जाता है।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में भी पोलियो टीकाकरण टीम को सुरक्षा प्रदान करने वाले दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। वहीं मार्च में इस्लामिक स्टेट की ओर से कहा गया था कि उसने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद में पोलियो टीकाकरण टीम से जुड़ी तीन महिलाओं की हत्या की है।

स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विला ला ग्रेंज में स्विस राष्ट्रपति गाय परमेलिन, केंद्र, राष्ट्रपति जो बिडेन, दाएं, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करते हुए।

कोरोना वायरस पर घिरे चीन में एक परमाणु प्लांट में रिसाव की आशंका, दुनिया से छिपा रहा, 10 लाख लोगों पर खतरा अधिक

हांगकांग । दुनियाभर में कोरोना महामारी फैलाने के आरोपों के बाद चीन अब नए विवादों में घिर गया है। दरअसल, चीन के एक परमाणु प्लांट में एक हफ्ते पहले रिसाव होने की शिकायत सामने आई। जिसे चीन ने दुनिया से छिपाकर रखा है। हांगकांग के एक नेता ने कहा कि ऐसी खबरें मिलने के बाद उनकी सरकार चीन के गुआंगदोंग प्रांत के ताइशन शहर में मौजूद परमाणु प्लांट पर बराबर नजर बनाए हुए है। इस शहर की आबादी करीब 10 लाख है। चीन के गुआंगदोंग प्रांत के ताइशन शहर में स्थित परमाणु प्लांट हांगकांग से महज 135 किलोमीटर दूर है। हालांकि यहां सोमवार की रात तक हांगकांग में विकिरण की कोई स्थिति नहीं है। ताइशन की आबादी पर तो तबाही का खतरा मंडरा ही रहा है। हालांकि अभी तक लीक की भयावहता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जबकि प्लांट के आपरेटरों ने कुछ ब्योरे दिए लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि उनसे मिली जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि एक परमाणु रिएक्टर में फ्यूल राडों से गैस लीक हो सकती है। सीएनएन की रिपोर्ट में भी परमाणु प्लांट में लीकेज होने का दावा किया गया है। ताइशन प्लांट में दिसंबर, 2018 से कर्मिशियल आपरेशन शुरू हुए थे। इस बीच, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि उनके परमाणु प्लांट में सुरक्षा को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। विकिरण स्तर में भी कोई असामान्यता नहीं देखी गई है।

चीन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए लीकेज का मामला उजागर होने के बाद अब एक नई बात सामने आई है। इस परमाणु संयंत्र के निर्माण में चीनी कंपनी जनरल न्यूक्लियर पावर ग्रुप (सीजीएन) के साथ हिस्सेदार फ्रांस की बिजली कंपनी ईडीएफ ने साफ किया कि उसे इस प्लांट में अज्ञात गैसों की जानकारी मिली थी। फ्रांस की ऊर्जा कंपनी का कहना है कि ताइशन के रिएक्टर नंबर एक से रिसाव हुआ चूंकि असामान्य गैसों की सघनता बढ गई थी।

कम राजस्व के चलते, अपने खर्चों में कटौती करेगी दिल्ली सरकार

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने गैर-जरूरी सरकारी खर्च को कम करने का जारी किया आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)।

कोरोना के कारण खर्चों के बढ़ने से दिल्ली सरकार ने खर्चों के प्रबंधन और रेशनलाइजेशन के लिए मेमोरेंडम आर्डर जारी किया है। ताकि युक्तिसंगत तरीकों को अपनाकर खर्चा को रेशनलाइज किया जा सके। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के पहले दो महीनों के दौरान दिल्ली सरकार के खर्च में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान दिल्ली की राजस्व प्राप्तियां 5,273.26 करोड़ रुपए रही हैं, जबकि खर्च 8,511.09 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इन दो महीनों में दिल्ली ने अपनी प्राप्तियों से 3,237.83 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए हैं जो पिछले साल की बचत से मिले थे। उपमुख्यमंत्री ने साझा किया कि वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान पहले 2 महीनों के खर्च 4705.14 करोड़ था, वित्तवर्ष 2020-21 में ये 4965.5 करोड़ था। कोरोना महामारी के कारण खर्चे तेज़ी से बढ़कर चालू वित्तवर्ष में 8511.09 करोड़ पहुंच गया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण कर संग्रह में गिरावट आई है। जबकि कोरोना काल में विभिन्न राहत कार्यों के कारण पिछले वर्षों की तुलना में खर्च में वृद्धि हुई है।

- दिल्ली सरकार के खर्च में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई
- कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण कर संग्रह में गिरावट आई
- नागरिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पर इस कटौती का कोई असर नहीं होगा

वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी कि खर्चों के बढ़ने के कारण दैनिक कार्यों में होने कार्यों व अन्य व्यय में कटौती करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि, दिल्ली के नागरिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पर इस कटौती का कोई असर नहीं होगा और वे पहले के समान चलती रहेंगी।

दिल्ली एक बार फिर से डूबने के कगार पर: आदेश गुप्ता

नई दिल्ली (संवाददाता)। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार द्वारा बरसात के पूर्व नालों की सफाई कराने का काम पूरा नहीं किया गया है जिससे दिल्ली एक बार फिर से बरसात के पानी में डूबने के कागार पर है। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में बरसात होने की संभावना है और प्री-मानसून भी पूरी तरह से आ चुका है। ऐसे में अभी तक नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है। नालों में से गाद निकालने का मुख्य काम पीडब्ल्यूडी विभाग का है जो अब तक काम करने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दिल्ली में 1400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों के दोनों ओर नाले-नालियों की सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में हल्की प्री-मानसून की बौछार ने ही केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी है और कई क्षेत्र पानी में डूबे पड़े हैं। ऐसे में आने वाले समय में सड़कों पर पानी जमा होना और कॉलोनियों में बाढ़ जैसा माहौल बनना तय है। आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पीडब्ल्यूडी और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग से नालों की सफाई को युद्धस्तर पर कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की आदत बन चुकी है कि वे अपने स्तर पर होने वाले कामों को पूरा करने में कोई रुचि नहीं दिखाते और अनहोनी पर नगर निगम और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराकर स्वयं बचकर निकलने का प्रयास करते हैं।

दिल्ली देश में बेरोजगारी दर में नम्बर वन पर पहुच गई है: अनिल

(संवाददाता)

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के लगभग 7 वर्षों के कार्यकाल में दिल्ली के लोगों की समस्याएं निरन्तर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने 2015 के घोषणा पत्र में 5 वर्षों में 8 लाख रोजगार देने का वायदा केवल लोगों को गुमराह करने के लिए किया था, जबकि देश सहित दिल्ली में बेरोजगारी की स्थिति पिछले 75 वर्षों में सबसे खराब है और दिल्ली में बेरोजगारी दर देश की औसत से 4 गुणा अधिक है। लेकिन भाजपा और आप पार्टी 75 साल की दुहाई देती हैं। चौ0 अनिल कुमार प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उनके साथ प्रदेश महिला अध्यक्ष अमृता धवन मौजूद थी।

संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली को नया शहर बनाने का दावा किया था और अपने सात वर्षों के शासन काल की उपलब्धियों में केजरीवाल ने बेरोजगारी, कोविड संक्रमण, कोविड मृत्यु दर, प्रदूषण, महिला उत्पीड़न में, शराब मुहैया कराने में, विज्ञापन पर खर्च करने में, झूठ बोलने पर और दिल्ली मंत्रियों और विधायकों को जेल जाने के मामले दिल्ली को नम्बर वन बना दिया है। उन्होंने कहा कि आज जहां देश में बेरोजगारी दर 11.4 प्रतिशत है वही दिल्ली में 45.6 प्रतिशत की बेरोजगारी दर है। जिससे साफ हो जाता है केजरीवाल के शासन में दिल्ली के लगभग आधे युवा बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार रोजगार निदेशालय ने 2015 से अगस्त 2020 तक सिर्फ 440 बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी है, जबकि दिल्ली सरकार में 55,000 पद खाली है जो रोजगार निदेशालय के अनुसार 84 प्रतिशत पद खाली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोजगार मुहैया कराने वाले रोजगार कार्यालय भी बंद होने की कगार पर है।

- दिल्ली में बेरोजगारी दर देश की औसत से 4 गुणा अधिक

चौ0 अनिल कुमार ने मांग की कि अरविन्द केजरीवाल दिल्ली में बढ़ती बेरोजगारी दर के अनुपात को कम करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर शहरी गारंटी रोजगार योजना कानून तत्काल बनाए ताकि प्रतिवर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार पूर्व आर्थिक सहायता देने के लिए उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उन्हांने कहा कि केजरीवाल सरकार की अनदेखी के चलते दिल्ली में युवाओं का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है और बढ़ती बेरोजगारी के कारण दिल्ली में अपराधिक मामले अधिक बड़ रहे है जिसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जिम्मेदार है।

संक्षिप्त खबर

टोयोटा किर्लोस्कर ने शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी

नई दिल्ली। ग्राहकों के अनुभव को बेहतर करने की अपनी सतत कोशिशों को मजबूत करते हुए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी तरह की पहली डोर डिलीवरी सेवा या विकल्प की शुरुआत की है। ग्राहकों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत उन्हें वास्तविक या असली पुर्जे खरीदने में सहूलियत होगी। यह टोयोटा पार्ट्स कनेक्ट का एक विस्तार होगा। यह कंपनी का एक प्रमुख आउटरीच प्रोग्राम है जिसका मकसद ग्राहकों की सहायता करना है ताकि वे 2015 में शुरू किए गए प्रमुख आउटरीच प्रोग्राम अभियान के तहत अपने वाजिब पुर्जों की उपलब्धता सुनिश्चत करें तथा टोयोटा के ग्राहकों को रुकावट रहित अनुभव मुहैया कराए। डोर डिलीवरी के विकल्प की शुरुआत के साथ ही ग्राहकों के पास यह विकल्प होगा कि वे गाड़ी के आवश्यक पुर्जे डीलरशिप से लें या घर पर डिलीवरी करवा लें। टोयोटा ने इस प्रोग्राम के तहत उत्पादों की रेंज में वृद्धि की है। इनमें कार केयर एसेनशियल्स, इंजन आयल और अन्य श्रेणियां हैं जिनके नाम हैं, टायर बैट्री आदि। यह सेवा इस समय 12 शहरों में उपलब्ध है और 2021 के अंत तक इसका विस्तार देश के सभी शहरों तक कर दिया जाएगा।

कोरोना की वजह से बुकिंग रद्द कराए जाने पर आईटीपीओ लगा रहा जुर्माना, छोटे व्यापारी परेशान

नई दिल्ली। कोरोना की वजह से इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) में होने वाले आयोजनों पर भी असर पड़ा है। जिसके तहत आईटीपीओ समेत कई निजी ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से कराए जाने वाले आयोजन भी स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में जिन ऑर्गेनाइजेशन ने आयोजन के लिए पहले ही भुगतान किया था, उनकी तरफ से कोरोना की वजह से बुकिंग रद्द कराए जाने पर आईटीपीओ जुर्माना लग रहा है। जिसे निजी ऑर्गेनाइजेशनों ने माफ करने की माफ की है। 25 फीसदी तक जुर्माना, एक हॉल पर 2 लाख रुपए तक हो रहा नुकसान
आईटीपीओ बुकिंग रद कराने पर आयोजकों पर कुल जमा राशि पर 25 फीसदी तक का जुर्माना लगा रहा है। इस संबंध में निजी आर्गेनाइजर राजेश कुमार बताते हैं कि आईटीपीओ हॉल बुकिंग के लिए अग्रिम भुगतान लेता है। अब कोरोना की वजह से जब आयोजन रद हो गए हैं, तो बुकिंग रद कराने पर आईटीपीओ 25 फीसदी तक जुर्माना लग रहा है।

मामूली विवाद के बाद चले दो लोगों के बीच हुई चाकूबाजी, एक घायल

नई दिल्ली। न्यू फ्रेंड कालोनी इलाके में एक घर के काम करने वाले दो लोगों के बीच मामूली कहासूनी के बाद चाकूबाजी हो गई। घर में ड्राइवर का काम करने वाले एक युवक ने उसी घर के काम करने वाली घरेलू सहायिका के पति को चाकू से गोद दिया। घायल जय सरकार को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने घायल के बयान पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी वासू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि न्यू फ्रेंड कालोनी स्थित एक घर में घायल जय सरकार की पत्नी घरेलू सहायिका का काम करती है और इसी घर में बने क्वाटर में परिवार के साथ रहती है। जय सरकार दर्जी का काम करता है। जबकि इसी घर में वासू कुमार ड्राइवर की नौकरी करता है। गुरुवार सुबह जय सरकार अपनी बाइक साफ कर रहा था। इसी दौरान ड्राइवर पर पानी गिर गया। जिसके बाद दोनों के बीच काहसूनी और हाथापाई होने लगी।

आप नेता संजय सिंह पर हमला नहीं, नेमप्लेट पर कालिख पोतने आए थे दो युवक; जांच में आया सामने

नई दिल्ली। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर मंगलवार दोपहर दो युवक केवल उनके नेमप्लेट पर कालिख पोतने आए थे। उन्होंने न तो संजय सिंह पर हमला किया था और न ही उनकी ऐसी कोई मंसा थी। दोनों राम मंदिर न्यास संस्था के कार्यकर्ता हैं। दोनों से पुछताछ व संजय सिंह के आवास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच से इसकी पुष्टि हो गई है।

कार्यकर्ताओं में एक का नाम अभिषेक दुबे व दूसरे का नाम सुरेंद्र कुमार है। अभिषेक, सहरसा, बिहार व सुरेंद्र, गली मंटोला, पहाड़गंज के रहने वाले हैं। घटना वाले दिन इन्हें पता लगा था कि संजय सिंह ने अपने आवास पर कुछ संवाददाताओं को अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन को लेकर बयान देने के लिए बुलाया है। उक्त सूचना पर दोनों ने संजय सिंह के आवास के बाहर लगे नेमप्लेट पर कालिख पोतने की योजना बनाई। दोनों अलग अलग बाइक से उनके घर के बाहर पहुच गए। वहां आकर उन्होंने देखा कि संजय

सिंह अपने लोन में कुछ मीडिया कर्मियों को बयान दे रहे थे।

ये अपने साथ स्याही लेकर आये थे। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इन्होंने तब नेमप्लेट पर कालिख पोती जब मीडिया कर्मी बाहर निकल गए थे। संजय सिंह के कार्यकर्ताओं ने दोनों को वहीं दबोच लिया और पुलिस को बुलाकर सौंप दिया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद शाम सात बजे उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था। पुलिस का कहना है की दोनो में कोई भी राज्यसभा सदस्य के आवास के अंदर नही धुसा था। उनकी ऐसी मंसा नहीं थी।

ज्ञात रहे संजय सिंह ने मंगलवार को घटना के बाद मीडिया को दिए बयान में आरोप लगाया था कि आरोपित उनकी हत्या करने के इरादे से सरकारी आवास के अंदर दाखिल हो गए थे। उन्होंने नार्थ एवेन्यू थाना पुलिस में लिखित शिकायत भी दे दी थी।

शिकायत में संजय सिंह ने कहा था कि दोपहर करीब 12 बजे उनके सरकार आवास 131, नार्थ ऐवन्यू में चार-पांच लोग जबरन दाखिल हो गए थे। उस वक्त वह अपने आवास के लोन में कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। वे लोग उन्हें जान से मारने की नियत से दाखिल हुए थे। आरोपितो ने उनके घर के बाहर लगे नेमप्लेट पर कालिख पोत दी और सरकारी संपत्ति को नुकासान पहुंचया। उनके घर में मौजूद लोगों ने दो लोगों को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था। उन्होंने भाजपा पर हमला करवा करने का आरोप लगाया था।

फीके पड़ते किसान आंदोलन में जान डालने के लिए किसानों को देने होंगे 100 रुपये

नई दिल्ली/सोनीपत। दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों का धरना-प्रदर्शन 28 नवंबर, 2020 से लगातार जारी है। किसान तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सोनीपत के गांव फरमाणा के शोभनाथ मंदिर परिसर में किसान मोर्चे की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने की।

हर गांव से 10 किसान आंदोलन स्थल पर जाएंगे - भारतीय किसान यूनियन की बैठक में सत्यवान नरवाल ने कहा कि आंदोलन को गति देने के लिए अब हर गांव में कमेटी गठित की जाएगी जो आंदोलनकारियों के लिए खाद्य सामग्री व आर्थिक मदद का इंतजाम करेगी। बैठक में फैसला लिया गया कि क्षेत्र के हर किसान से प्रति एकड़ सौ रुपये एकत्रित कर आंदोलन को चंदा दिया जाएगा और प्रतिदिन हर गांव से 10 किसान आंदोलन स्थल पर जाकर मनोबल बढ़ाएंगे।

बैठक में सर्वसम्मति से भोलू पहलवान को भाकियू का ब्लाक युवा अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर दादरी जिला प्रधान सुधीर डागर, सोनीपत जिला प्रधान अशोक लठवाल, गन्नौर ब्लाक प्रधान रवींद्र,खरखौदा ब्लाक प्रधान जय सिंह दहिया, बलबीर सेहरी, गहलावत अठगामा प्रधान सतबीर, सुरेंद्र, राजू, सुभाष निरथान, जोगिंद्र सिंह, बीरबल, सतबीर, राम सिंह और देवेंद्र मौजूद रहे।

वहीं, पिछले दिनों उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि कुंडली-सिंघु बार्डर पर जारी आंदोलन में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ट्रैफिक जाम की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हुए समाधान के लिए बाहरी ट्रैफिक के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। नेताओं ने कहा कि स्थानीय लोगों को विशेष छूट दी जाए, लेकिन दिल्ली जाने के लिए अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग दिया जाए। साथ ही उन्होंने सर्विस रोड को दुरुस्त करने की मांग की। नेताओं ने आंदोलन स्थल पर बिजली व सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा फॉगिंग करवाने की मांग की।

भाजपा ने बस खरीद घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की

नई दिल्ली (संवाददाता)।

भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बसों की खरीद में हुए करोड़ों रुपए की घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए इसके लिए जिम्मेदार परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के इस्तीफे की मांग की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक विजेंद्र गुप्ता और प्रदेश महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल सरकार द्वारा हर विभाग में बड़े स्तर पर घोटाला करने और करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधी विभाग को डीटीसी बसों की

खरीद घोटाले की जांच की अनुमति नहीं दे रही है। इन नेताओं ने कहा कि ऐसे में वे इस मामले को केंद्रीय भ्रष्टाचार आयोग के पास ले जाएंगे और चाहेंगे कि सारे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। प्रेसवार्ता में प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार मौजूद रहे। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में आज 15000 बसों की जरूरत है लेकिन पिछले 7 सालों में केजरीवाल सरकार ने एक भी बस की खरीद नहीं की। आज जितनी बसें दिल्ली की सड़कों पर चल रही है उनमें से सभी बसें सितंबर तक सड़कों से हटा ली जाएगी क्योंकि उनकी मियाद पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार इन बसों को फिर से सड़कों पर नहीं उतारा जा सकेगा। इसलिए एक तरफ दिल्ली में बसों की भारी कमी हो जाएगी जबकि नई बसों की खरीद में घोटालों के चलते स्वयं सरकार ही बसों की खरीद पर रोक लगा दी है। विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि हम बस खरीद में हुये भारी घोटालों का मुद्दा पिछले साल से उठाते आ रहे हैं। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया था और हाल ही में उपराज्यपाल से भी इस घोटाले की जांच कराने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली में भारी बारिश के बाद आरएमएल अस्पताल के पानी से भरे फर्श पर झाड़ू लगाता एक कर्मचारी।

दुकानों पर समय से राशन पहुंचा पाने में भी विफल हो रही दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। एक तरफ स्कूलों में पड़ा अनाज सड़ रहा है तो दूसरी ओर सरकारी दुकानों पर राशन पहुंचा पाने में भी दिल्ली सरकार विफल साबित हो रही है। आलम यह है कि जून का आधा माह बीत गया है, जबकि दिल्ली की आधी से अधिक दुकानों पर अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मिलने वाला मासिक राशन पहुंचा ही नहीं है। कार्ड धारक यही पता करने के लिए दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं कि राशन आया या नहीं। एनएफएसए 2013 के मुताबिक, हर माह की एक तारीख से राशन बंटना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन, समय से दुकानों पर आपूर्ति न होने के कारण ऐसा हो ही नहीं पाता। इसी माह की बात करें तो 13 जून तक दिल्ली की कुल 2008 दुकानों में से केवल 330 दुकानों पर एनएफएसए का राशन पहुंचा था। यहां बता दें कि जो राशन फिलहाल ज्यादातर दुकानों पर बंट रहा है, वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाइ) का है, एनएफएसए का नहीं।

जानकारी के मुताबिक एनएफएसए के तहत दो हजार से अधिक दुकानों पर राशन की आपूर्ति दिल्ली में ही स्थित फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एफसीआइ) के छह गोदामों से होती है। इन

गोदामों से दुकानों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन (डीएससीएससी) द्वारा सूचीबद्ध ट्रांसपोर्ट ठेकेदार करते हैं। लेकिन, इनकी संख्या भी पर्याप्त न होने के कारण राशन कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन दुकानों पर 100 फीसद खाद्यान्न पहुंच जाता है, पहले उनकी सूची आइटी ब्रांच द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद फूड एंड सप्लाई अफसर (एफएसओ) व इंस्पेक्टर द्वारा चिह्नित दुकानों पर जाकर जांच की जाती है कि दुकान में पूरा राशन मौजूद है या नहीं। इसके बाद ही उसके वितरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

हैरत की बात यह भी है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के आदेश के मुताबिक इस बार भी राशन मैन्युअली ही वितरित किया जा रहा है। सिर्फ सर्किल 63 सीमापुरी में ही इलेक्ट्रिक प्वाइंट आफ सेल (ई-पोस) मशीनों के जरिये राशन वितरित किया जा रहा है, जबकि केंद्रीय खाद्य आपूर्ति सचिव द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बायोमैट्रिक यानी ई-पोस के द्वारा दिल्ली भर में राशन वितरित किए जाने का निर्देश दिया गया था। इसके पीछे मंशा यह है कि अन्य राज्यों की तरह यहां भी वन नेशन- वन राशन कार्ड योजना को प्रारंभ किया जा सके।कोटमाह के 15 दिन बीत जाने पर भी 72 लाख लाभार्थियों को एनएफएसए राशन अभी तक नहीं मिल पाया है।

शिव कुमार गर्ग (अध्यक्ष, दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ) के मुताबिक, विभागीय सुस्ती का सामना राशन कार्डधारियों को करना पड़ रहा है। साथ ही ई-पोस मशीनें दुकानों में जनवरी 2021 से धूल फांक रहीं हैं। केंद्र सरकार का कहना भी नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि 10 लाख परिवार जो अन्य प्रदेशों से राजधानी में आए हैं, उनको वन नेशन- वन राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

थर्ड वेव की आशंका, बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे आइसोलेशन सेंटर

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बहुत से बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है. इस तरह के बच्चों के लिए दिल्ली सरकार ने जहां फिलहाल दो आइसोलेशन एवं क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं. वहीं, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने के लिए सभी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भी आने वाले समय में आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी भी की है. ऐसा कोरोना की संभावित थर्ड वेव को लेकर किया जा रहा है.

दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार कोआर्डिनेशन बनाकर और मीटिंग करके आने वाले समय में बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए बड़ी तैयारियों में जुटा हुआ है. महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत राजधानी में 26 सरकारी और 75 एनजीओ की ओर से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस संचालित हो रहे हैं. इन सभी चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन में भी आने वाले समय में थर्डवेव को लेकर आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी है. दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का भी कहना है कि फिलहाल विभाग के अंतर्गत लड़कों के लिए लाजपत नगर में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है. वहीं, लड़कियों के लिए जोनापुर में यह आइसोलेशन सेंटर चल रहा है.

मंत्री का कहना है कि अब यहां काफी कम बच्चे हैं. इनको आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है. आइसोलेशन सेंटर में 14 दिन के बाद उनकी जांच आदि सभी होने के बाद सीसीआई में भेज दिया जाता है. खासकर इनमें वह बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स की कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जान चली गई और इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है.

मंत्री का कहना है कि कोविड-19 के दौरान इस तरह की समस्या ज्यादा आई थी जिसके बाद यह दो सेंटर खोले गए थे. इनमें 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए व्यवस्था की गई थी. लेकिन आने वाले समय में बच्चों के लिए कोरोना की थर्डवेव के ज्यादा खतरनाक बताए जाने के बाद इस सभी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सभी इंस्टीट्यूशंस में आइसोलेशन सेंटर बनाने को WCD हेल्थ विभाग के साथ बनाए हुए है तालमेल

उनका कहना है कि सभी चिल्ड्रन होम में आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं. वहीं, थर्ड वेव के चलते बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी आइसोलेशन सेंटर बनाने की पूरी तैयारी है. इसके लिए सरकार के पास सेंटरों में पर्याप्त स्थान भी है. इस मामले पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ भी WCDविभाग पूरी तरीके से कोआर्डिनेशन बनाए हुए हैं.

संपादकीय

हमें मित्र नौकरशाही चाहिए

छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों से एक जैसे दृश्य दिखे। एक-दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद सरकारी तंत्र की सामान्य जन को लेकर सोच में अद्भुत समानता दिखी। छत्तीसगढ़ के एक कलक्टर साहब ने लॉकडाउन के दौरान दवा खरीदने के लिए सड़क पर निकले व्यक्ति को पहले तो खुद झपड़िया दिया और फिर अपने साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों से बेंत भी पड़वाए। दूसरे कलक्टर त्रिपुरा में एक शादी के मंडप में दूल्हे के अलावा उसके परिजन और पंडित पर हाथ उठाते दिखे। उत्तर प्रदेश तो एक से अधिक मौकों पर लॉकडाउन तोड़ने वाले ठेले-खोमचे वालों को पीटते या फिर उनका सामान सड़क पर फेंकते पुलिसकर्मी हमें दिखे। गनीमत है, इस बार सोशल मीडिया की उपस्थिति ने इस अमानवीयता की परतें उघाड़कर उसे ढका-छिपा नहीं रहने दिया। ऐसा क्योंकर हुआ कि भारत में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सरकारी तंत्र आमजन को एक सामान भेड़-बकरी मानता है। जैसी नौकरशाही या पुलिस अंग्रेज बहादुर छोड़ गए थे, उसमें बुनियादी परिवर्तन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अभी भी नौकरशाह माई-बाप हैं और जनता उसके सामने हाथ जोड़कर उकड़ू बैठी याचक भिखारी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसे सामाजिक स्वीकृति हासिल है। मुझे याद है, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री अधिकारियों की बैठकों में कहा करते थे कि सरकार तो अपने इकबाल से चलती है और यह हनक से पैदा होता है। उनकी बैठक से लौटकर मैं हनक शब्द के अर्थ तलाशने लगा था। शब्दकोशों में दिए गए अर्थ आपके बहुत काम नहीं आते हैं, उनके लिए तो लौकिक समझ की शरण लेनी पड़ती है। लोक हनक से भय या आतंक का रिश्ता जोड़ता है। कई रोचक संस्मरण याद आ रहे हैं। अपनी नौकरी की शुरुआत में ही मुझे एक मनोरंजक शिकायत से पाला पड़ा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से एक फरियादी शिकायत कर रहा था कि उसके थाने में जिस थानेदार को तैनात किया गया है, वह तो बड़ा 'सज्जन' है। सुनने वाले थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, उन्होंने ठिठोली की कि उस थाने में तो सौ से अधिक हिस्ट्रीशीटर हैं, क्या उनमें से किसी को थाने का चार्ज सौंप दिया जाए। 'सज्जन' होना कितना बड़ा दुर्गुण है, यह तो मुझे बाद में अपनी नौकरी के दौरान एहसास हुआ। भाषा बोलने वालों के समाजबोध का सबसे बड़ा दर्पण होती है। किसी थानेदार की कामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण भाषा में व्यक्त करते हुए कहा जाता है कि पूरा इलाका उसके सामने छड़ी की तरह खड़ा रहता है। किसी सभ्य समाज में शायद यह कहा जाता कि आमजन उसे अपना दोस्त या मददगार समझते हैं। छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा के कलक्टरों के वीडियो एक गंभीर समाजशास्त्रीय विमर्श की अपेक्षा रखते हैं। वीडियो में उनकी जो तस्वीरें दिखती हैं, वे नौजवानों की हैं। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि तीस-पैंतीस वर्ष के ये कलक्टर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस पास कर एक ऐसी दुनिया में आए हैं, जिसमें रहकर वे असंख्य लोगों की जिंदगी में फर्क पैदा कर सकते हैं। उनकी उम्र भी ऐसी है कि विश्वविद्यालयों में हासिल किया गया आदर्शवाद अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ होना चाहिए। फिर कैसे वे दवा का परचा दिखाने के बावजूद एक असहाय को सड़क पर पीट सकते हैं। हमें उन पर गुस्से से अधिक तरस आनी चाहिए। वे इसलिए भी दया के पात्र हैं कि उन्होंने यह मूल्य अपने आसपास की दुनिया से हासिल किया है। जिस समाज में उन्होंने आंखें खोलीं, वहीं उन्हें सिखाता है कि अच्छा प्रशासक वही है, जिसकी हनक हो और हनक पैदा करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि आप किसी असहाय व्यक्ति को बीच सड़क पर लठिया दीजिए। त्वरित न्याय से ही सरकार का 'इकबाल' बुलंद होता है, इसलिए वे विवेचक, अभियोजक और जज, तीनों की भूमिका एक साथ निभाने लगते हैं। तंत्र की अमानवीयता या कानून-कायदे की धज्जियां उड़ाने को जो सामाजिक स्वीकृति हासिल है, वह इन अधिकारियों को एक बार भी यह एहसास नहीं होने देता कि वे कुछ गलती कर रहे हैं। उन्हें भी तो बचपन में मां ने न सोने पर डरवाया होगा कि सो जाओ, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। कोई मां अपने बच्चे को सलाह नहीं देती कि अगर उसे सड़क पर किसी मदद की जरूरत हो, तो वह फौरन पुलिस के पास जाए। सूचना तंत्र के विस्फोट ने थोड़ा फर्क डालना शुरू कर दिया है, पर सोचने के बुनियादी तरीके में कोई बड़ा फर्क आया हो, ऐसा नहीं लगता। ऊपर जिन घटनाओं का जिक्र आया है, उनमें सम्मिलित कलक्टरों या पुलिसकर्मियों के विरुद्ध शोर-शराबे के बाद बड़ी अनिच्छा के साथ राज्यों ने कार्यवाही की है। किसी मुख्यमंत्री ने पीड़ित से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी है। शायद यह तो हमारी परंपरा के ही खिलाफ है। अपनी परंपरा के अनुकूल हम यह जरूर पाते हैं कि सोशल मीडिया पर सरकारी तंत्र की गलती को उजागर करने वाले के ही खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने लगी हो। सबसे बड़ा उदाहरण तो कोरोना की पिछली लहर में उत्तर प्रदेश में मिला जब मरीजों को अपने साथ मोबाइल फोन रखने से मना कर दिया गया। कारण साफ था कि मरीज अपने वार्डों की दुर्दशा वीडियो बनाकर उजागर करने लगे। सरकार के उच्च पदों पर बैठे मान्यवरों को खुश होना चाहिए था कि उन्हें जमीनी यथार्थ की जानकारियां मिल रही हैं, पर उन्हें जनता के इस दुस्साहस पर नाराजगी हुई कि वह उन्हें आईना दिखा रही है और उन्होंने इस प्रयास को ही प्रतिबंधित कर दिया। मोबाइल न रखने का आदेश दुनिया भर की चिकित्सीय सलाहों के विरुद्ध था, जिसमें एकांत में पड़े मरीजों को सकारात्मक रखने के लिए बाहरी दुनिया के संपर्क में रहने की बात की गई थी। यह तो छीछालेदर के बाद ही सरकार को शर्म आई और मोबाइल न रखने का आदेश वापस लिया गया। हाल में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के जो प्रयास हो रहे हैं, उन्हें इसी मानसिकता का उदाहरण माना जाना चाहिए। सरकारें कभी किसी अभद्र कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करती भी हैं, तो उनकी देहभाषा से समझ में आ जाता है कि ऐसा वे बड़ी अनिच्छा से कर रही हैं। बहुत हल्ला होने और यह समझ में आने के बाद कि अब बचाना मुश्किल है, दोषी के विरुद्ध कार्यवाही होती है। एक बार शासकों की मंशा स्पष्ट हो जाए कि उन्हें एक सभ्य और जनता की मित्र नौकरशाही चाहिए, तो यह विमर्श बदल सकता है, पर इसके लिए एक लंबे अभ्यास की जरूरत होगी।

प्रवीण कुमार सिंह

न्यायिक सक्रियता से ही संभव है प्रकृति का संरक्षण और आर्थिक विकास

सबसे महत्वपूर्ण यह था कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप निर्देश दिया कि बोनस और ऐसा मुआवजा उस मुआवजे के अतिरिक्त होगा जो कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत दिया जाता है। इसी प्रकार, प्रदूषण नियंत्रण और इस समस्या के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए न्यायालय ने 'एहतियाती सिद्धांत' और 'प्रदूषक भुगतान करेगा' सिद्धांत की भी व्याख्या की है। एहतियाती सिद्धांत साक्ष्यों के कानून तहत पर्यावरणीय मामलों में प्रमाण भार से संबंधित है। न्यायालय ने इस सिद्धांत के तहत यह कहा कि प्रदूषक का यह दायित्व होगा कि वह यह प्रमाणित करे कि उसके किसी कार्य, उद्योग या किसी गतिविधि से स्वास्थ्य या पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेकर अपनी परंपरा का पालन करेंगे, लेकिन वही प्रश्न अब भी गंभीर बना हुआ है कि क्या हम अपने इस संकल्प को यथार्थ का रूप देंगे? कोविड महामारी और हाल ही में आए दो तूफानों ने फिर यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति पर गहराया संकट दिन-प्रतिदिन और गंभीर होता जा रहा है। सेमिनारों और गोष्ठियों में पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा कर अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हमारा दायित्व पूरा हो गया है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में निश्चित रूप से संवैधानिक प्रविधानों और न्यायालय के प्रयासों का योगदान महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में शामिल संबंधित प्रविधानों पर गौर करने से पहले हम यहां महात्मा गांधी के एक ऐसे विचार पर गौर करेंगे जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। गांधीजी ने कहा है, 'पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं।' इसका अर्थ यह है कि प्रकृति जीवन रक्षण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन यदि हम अपने स्वार्थ के लिए उनका अति दोहन करेंगे तो एक ओर उससे पर्यावरणीय क्षरण होगा और दूसरी ओर वह मानव के अस्तित्व पर भी गंभीर संकट उत्पन्न करेगा। इस पृष्ठभूमि में संवैधानिक प्रविधानों के जरिए यह समझना आवश्यक है कि हमें क्या करना चाहिए। मानव पर्यावरण की सुरक्षा पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। भारत द्वारा इसका अनुमोदन किए जाने के बाद वर्ष 1976 में 42 वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 48 (ए) और अनुच्छेद 51 (ए) जोड़ा गया जिनमें क्रमश- राज्य और नागरिकों को पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। इसके

अतिरिक्त, इस संशोधन ने राज्य सूची के कई विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया, जैसे प्रविष्टि 17(ए) में वन, 17(बी) में वन्य जीवन तथा 20(ए) में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन।चूंकि भारत के संविधान में नैसर्गिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, अत- यह हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरणीय सुरक्षा कर ऐसे न्याय की उपलब्धता में राज्य को समर्थन दें। पिछले कुछ दशकों में विशेषकर बाजार अर्थव्यवस्था के प्रसार के बाद हम अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हुए हैं। अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता निश्चित रूप से एक विकसित समाज का अभिन्न अंग है, लेकिन यह भी सत्य है कि अधिकारों की बढ़ती मांग संघर्षों का प्रमुख कारण भी बनती है। कारण यह कि हम अधिकारों की मांग करने पर अत्यधिक जोर देने के फलस्वरूप कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। शायद इसी स्थिति ने पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता नहीं बढ़ पाने में योगदान दिया है।

कर्तव्यपरायणता राष्ट्र विकास का सबसे सुदृढ़ मार्ग है। यही राष्ट्रवाद की सुदृढ़ता का आधार है। यहां राष्ट्रवाद को सैद्धांतिक रूप में नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप में समझने की आवश्यकता है। यदि हम अपने स्तर पर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो हम राष्ट्र विकास में सीधे तौर पर योगदान दे सकेंगे। इन्हीं कर्तव्यों में पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्य भी शामिल होंगे। हम ऐसे दृष्टिकोण को उत्तर-लोकतांत्रिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा कर्तव्य का पालन करने से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार की रक्षा होती है। कारण यह कि अधिकार और कर्तव्य सह-संबंधी हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हम अन्य व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। और उनके द्वारा ऐसा करने पर हमारे अधिकारों की सुरक्षा की संभावनाएं अधिक होंगी।

यही दृष्टिकोण नागरिकों और राज्य के बीच भी प्रचलित होना चाहिए। अर्थात पर्यावरण क्षरण की विभीषिका और सामाजिक-र्आथिक संघर्षो की बढ़ती भयावहता की पृष्ठभूमि में अधिकार आधारित दृष्टिकोण के बदले कर्तव्य आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाने की नितांत आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। इस दिशा में यदि न्यायपालिका की भूमिका पर विचार करें तो यह स्पष्ट होगा कि न्यायालयों ने पहलकारी प्रयासों के जरिए न केवल अधिकारों का संरक्षण किया है और नए अधिकारों की पहचान की है, बल्कि उसने राज्य और नागरिकों को अपने दिशा निर्देशों यहां तक कि कई अवसरों पर आदेशों के माध्यम से उन्हें जवाबदेह और कर्तव्यनिष्ठ बनाने का भी प्रयास किया है। एमसी मेहता बनाम कमल नाथ 1997 मामले में न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 का निर्वचन कर जन-न्यास एवं पारिस्थितिकी सिद्धांत की व्याख्या की। इसके अनुसार, राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी संसाधनों के लिए राज्य एक न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में कार्य करेगा, न कि उनके स्वामी के रूप में और इनका उपयोग केवल जन कल्याण के लिए ही किया जाएगा।

इसी प्रकार से गंगा नदी से संबंधित प्रदूषण के मामले में वर्ष 1987 में यह कहा गया था कि चमड़े के कारखानों को स्थानांतरित किए जाने से हालांकि बेरोजगारी उत्पन्न होने की आशंका होगी, लेकिन जीवन, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी नागरिकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य की महत्ता तो हमने कोविड संकट के दौरान समझ ही ली है। हालांकि इसे न्यायिक अति सक्रियता कह कर इसकी आलोचना की गई, लेकिन पूर्वाग्रह रहित होकर विचार करने से न्यायालय के दृष्टिकोण का महत्व स्पष्ट हो जाएगा। न्यायपालिका ने अपने एक पहलकारी प्रयास के द्वारा यह निर्देश दिया कि भारत में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा शामिल होनी चाहिए। साथ ही, पर्यावरण सुरक्षा को राज्य और नागरिकों पर एक सामाजिक बाध्यता बनाया जाना चाहिए।

पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक विकास पर्यावरण सुरक्षा तथा र्आथिक विकास और अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की दृष्टि से ताज ट्रैपीजियम मामला (एम सी मेहता बनाम भारत संघ 1997) अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने श्रम पर्यावरण विधिशास्त्र (लेबर एनवायरमेंटल जूरिस्प्रुडेंस) की एक नई संकल्पना विकसित की। अपने निर्णय में न्यायालय ने ताजमहल की सुरक्षा के लिए उसके निकट अवस्थित कोयला और डीजल उपयोग करने वाले उद्योगों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इन उद्योगों के कर्मचारियों को स्थानांतरण बोनस दिया जाएगा। बंद होने वाले उद्योगों के कर्मचारियों को छह वर्ष के भत्ते के बराबर मुआवजा भी दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप निर्देश दिया कि बोनस और ऐसा मुआवजा उस मुआवजे के अतिरिक्त होगा जो कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत दिया जाता है।

इसी प्रकार, प्रदूषण नियंत्रण और इस समस्या के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए न्यायालय ने 'एहतियाती सिद्धांत' और 'प्रदूषक भुगतान करेगा' सिद्धांत की भी व्याख्या की है। एहतियाती सिद्धांत साक्ष्यों के कानून तहत पर्यावरणीय मामलों में प्रमाण भार से संबंधित है। न्यायालय ने इस सिद्धांत के तहत यह कहा कि प्रदूषक का यह दायित्व होगा कि वह यह प्रमाणित करे कि उसके किसी कार्य, उद्योग या किसी गतिविधि से स्वास्थ्य या पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी।

यदि स्वास्थ्य-शिक्षा की अनदेखी होती रही तो गरीबी उन्मूलन का सपना उलझा रहेगा

जनता के लिए प्रत्येक चुनाव अपनी मांगों को सामने रखने का एक अवसर भी होता है। इसमें जब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मांग होती है तो मतदाता अस्पताल की मांग करते हैं। अमूमन इस मांग के केंद्र में उनके मन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जैसे मेडिकल संस्थान की छवि होती है। हालांकि एक बढ़िया अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति के अंतिम पड़ाव का केंद्र होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक अस्पताल जाने से बचता है, जब तक कि उसके अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। यानी एक तरह से संकट का समय ही अस्पताल जाने की वजह बनता है। मौत को टालने की हमारी बेचैनी में हम स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक उद्देश्यों की अक्सर अनदेखी कर जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य जीवन को पोषित करना ही होना चाहिए। निस्संदेह अस्पताल आवश्यक हैं, लेकिन वे इस कहानी का अंतिम हिस्सा ही हैं।

औषधि विज्ञान के तीन आयाम हैं। पहला रोकथाम, जिसमें महामारी या भीषण बीमारी के लिहाज से जोखिम वाले वर्गों के लिए टीकाकरण जैसे उपाय करना। दूसरा सहज उपलब्ध दवाओं, किफायती औषधियों से उपचार संबंधी कदम। इसमें अंतिम और तीसरा होता है संकट प्रबंधन। भारतीयों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए स्वतंत्र भारत के पहले बजट से ही उपरोक्त बिंदुओं में शुरुआती दो से जुड़ी अवसंरचना में भारी निवेश की दरकार थी, परंतु स्वास्थ्य नीतियों में उनका समावेश पिछली सदी के नौवें दशक में ही संभव हो सका। विगत सदी के अंतिम दशक में प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के बाद ही भारत ने दवाओं का उत्पादन आरंभ किया। तब तक उत्पादन राज्य की अक्षमताओं और राष्ट्र की प्रगति में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने की अनिच्छा के कारण अटका रहा। इसके चलते हमारा पूरा ध्यान अस्पतालों पर केंद्रित रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे नेता रहे, जिन्होंने गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता में शामिल किया। इसके लिए बीमा जैसा व्यावहारिक विकल्प अपनाया गया। यह विगत सात वर्षों के दौरान विकसित किया गया, जो उनके नीतिगत ढांचे का एक उल्लेखनीय पहलू रहा। इसका खाका व्यापक स्तर पर जीवन गुणवत्ता सुधारने के इर्दगिर्द ही खींचा गया है। भारतीय शासन संचालन यानी गवर्नेंस की एक बड़ी विसंगति यह रही है कि उसके नीति निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन से गरीब तबका गायब रहा है। मैं केवल प्रशासनिक सेवाओं की ही बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मसला आर्थिक गवर्नेंस का भी है। इसमें निजी क्षेत्र और मीडिया शामिल है, जो विचार-समझ और सामाजिक सेवाओं को प्रभावित करते हैं। यहां हमें एक विरोधाभासी तथ्य भी स्वीकार करना होगा और वह यह कि हमारे चुनावों की नियति तो गरीब तय करते हैं, लेकिन प्रशासनिक शक्ति का नियंत्रण सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न अभिजात्य वर्ग के हाथ में होता है।

महज भली मंशा या नेक नीयत से ही हम इस स्थिति को नहीं बदल सकते। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस दिशा में पहला कदम यही होगा कि गरीबों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कमी के कारण गहराते गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालें। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के बिना उनकी आकांक्षाओं को पंख लगाने की कोई भी उम्मीद बेमानी है। ईश्वर ने गरीब और अमीर दोनों को बराबर अक्ल दी है, लेकिन गरीबों को शिक्षा से वंचित रखा गया, जबकि उसके माध्यम से ही वे अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे बेहतर और उत्पादक उपयोग कर पाएंगे।

इसके बावजूद यह समझ पाना मुश्किल है कि साक्षरता को सरकार का घोषित उद्देश्य बनाने में पिछली सदी के नौवें और आखिरी दशक तक की देरी क्यों की गई? वर्ष 1947 या बीती सदी के छठे दशक में ही इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों नहीं बनाया गया? उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा कभी नीति-नियंताओं के वरीयता प्राप्त एजेंडा का हिस्सा क्यों नहीं रही? अगर हमने पिछली सदी के सातवें दशक तक भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को शिक्षित कर लिया होता तो आज गरीबी गायब हो गई होती। लोगों ने भीषण गरीबी से बाहर निकलने के लिए हाथ-पैर मारे होते, लेकिन हमने उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक उपकरण ही नहीं उपलब्ध कराए। हमने उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा।

जहां तक स्वास्थ्य ढांचे का प्रश्न है तो कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे की उपेक्षा के सच्चे अतीत को उजागर करने का काम किया है। चूंकि शिक्षा की कमी से लोग मरते नहीं तो इसे महामारी के तौर पर नहीं देखा जाता, परंतु हम उस नुकसान को महसूस करने में भी नाकाम रहे हैं, जो अशिक्षा के कारण पहुंचता है। असल में सबसे बेहतरीन और बदतरीन उपलब्ध शिक्षा के बीच जो अंतर होता है, वह जानबूझकर भूलने की आदत में दफन है।

तमाम संकेतकों के दृष्टिकोण से सांख्यिकी उपयोगी है, लेकिन तथ्यों को लेकर भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार देश में गरीबों की संख्या सिकुड़कर करीब 25 करोड़ रह गई है। फिर भी 25 करोड़ का यह आंकड़ा भारत से कहीं अधिक क्षेत्रफल वाले देश रूस की कुल आबादी से 10 करोड़ अधिक है। दरअसल हम भूख सूचकांक आधार पर ही गरीबी का आकलन नहीं कर सकते। यह समझने की जरूरत है कि यह एक न्यूनतम मानक है।

तीसरी लहर में बच्चे

चिकित्सा जगत की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका लैंसेट की यह स्टडी रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। %लैंसेट कोविड-19 कमिशन इंडिया टास्क फोर्स% ने एक्सपर्ट्स ग्रुप की मदद से दोनों लहरों के दौरान अस्पतालों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कहा है कि भारत में बच्चों के संक्रमण की स्थिति कमोबेश वैसी ही रही है, जैसी दुनिया के अन्य हिस्सों में। औसतन पांच लाख संक्रमित बच्चों में 500 को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, इनमें भी दो फीसदी की मौत हुई। मौत वाले इन मामलों में 40 फीसदी केस ऐसे थे. जिनमें बच्चे दूसरी गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त थे। इसलिए स्टडी ग्रुप की साफ राय है कि तीसरी लहर को बच्चों के लिए विशेष तौर पर खतरनाक मानने की कोई वजह नहीं है। दरअसल, दूसरी लहर ने देश में जिस तरह के भयावह हालात बना दिए थे, उसमें आम लोगों के बीच तरह-तरह की आशंकाएं पैदा होना स्वाभाविक था। इसी माहौल में कुछ एक्सपर्ट ग्रुप्स की तरफ से भी ऐसे बयान आए, जिनसे आशंकाओं को बल मिला। तीसरी भयावह लहर आने और उनमें बच्चों के लिए खास खतरा होने की बात ऐसी थी, जिसकी किसी भी सूरत में अनदेखी नहीं की जा सकती थी। हालांकि ऐसी आशंका जताने के पीछे कोई गलत इरादा था, यह नहीं कहा जा सकता। चूंकि दूसरी लहर में अपेक्षाकृत युवा मरीजों की मौत का अनुपात अधिक देखने में आ रहा था, इसलिए कुछ विशेषज्ञों को ऐसा लगा कि संभव है तीसरी लहर में और कम उम्र के लोग इसकी चपेट में आएं। सरकारी तंत्र और आम लोगों को आगाह करने के इरादे से उन्होंने अपनी यह राय सार्वजनिक कर दी। मगर इतनी अहम लड़ाई में हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की जरूरत होती है। इन बयानों के बाद जहां आम लोगों में भय और आशंका की भावना भरने लगी, वहीं हेल्थकेयर ढांचे में भी बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने की तैयारियां शुरू हो गईं। संसाधनों की सीमा को देखते हुए अगर अवैज्ञानिक सूचनाओं के आधार पर तैयारियां जारी रखी जाएं तो फिर ज्यादा जरूरी तैयारियां छूट जाने का खतरा रहता है। ऐसे में लैंसेट की यह रिपोर्ट जहां हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य के मोर्चे पर अनावश्यक आशंकाओं से मुक्त करती है, वहीं संसाधनों की संभावित बर्बादी भी रोक सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि आम लोगों के अलावा एक्सपर्ट समूहों को भी सावधान करती है कि गंभीर अध्ययन, जांच-पड़ताल और ठोस सबूतों की रोशनी में कोई बात की जाए तभी उसका वैज्ञानिक महत्व है। और, वायरस से लड़ाई के बीच में किसी भी वजह से वैज्ञानिकता का साथ छोड़ना आत्मघाती हो सकता है।

परीक्षा का सार्थक विकल्प शिक्षा को उसकी अनेक बाधाओं से करेगा मुक्त

बौद्धिक योग्यता की प्रामाणिकता अपने परिवेश, समाज और प्रकृति के साथ रहने और अनुकूलन की व्यावहारिक उपलब्धि में ही प्रकट होती है। जो क्रियावान होता है, वही विद्वान होता है। इस दृष्टि से अब आभासी शिक्षण की दुनिया में रिमोट परीक्षा के एक सार्थक माडल को विकसित करना होगा, जिसमें स्मरण, समझ, विश्लेषण, सृजन और निर्णय आदि को सीखने के व्यापक परिवेश में स्थापित करना जरूरी होगा। इस दिशा में देश-विदेश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में प्रयोग चल रहे हैं। छात्रों को अपनी क्षमता व्यक्त करने का समुचित अवसर देना परीक्षा के भूत से मुक्ति दिलाने में निश्चित रूप से सहायक होगा, जो मानसिक रुग्णता और पारिवारिक तनाव का एक बड़ा कारण बना रहता है। परीक्षा का सार्थक विकल्प शिक्षा को उसकी अनेक बाधाओं से मुक्त करेगा।

कोरोना वायरस की उलटी-सीधी चाल के चलते लंबी खींची कोविड महामारी के बीच हो रही उठापटक में चाहे-अनचाहे देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक जीवन की अब तक की स्वीकृत सामान्य व्यवस्थाओं में बहुत सारे बदलाव करने पड़ रहे हैं। इसके फलस्वरूप अब हर किसी को नए सिरे से अपने को व्यवस्थित करना जरूरी होता जा रहा है। हमारे विकल्प सीमित-संकुचित होते जा रहे हैं और हमें नई शर्तों के साथ जीने का अभ्यास करना पड़ रहा है। कोरोना के दौर में मजबूरी में ही सही, हमें स्वदेशी, स्वावलंबन, संतोष और संयम जैसे पुराने पड़ रहे शब्दों का अर्थ फिर से समझना पड़ रहा है। चूंकि कोविड महामारी आने के पहले की अवस्था में शिक्षा संस्थाएं चल रही थीं, पढाई-लिखाई के नाम पर प्रवेश और परीक्षा का कार्यक्रम विधिवत संपादित हो रहा था। विद्यार्थी, अध्यापक और पालक सभी प्रचलित व्यवस्था का आदर करते हुए उस पर अपना भरोसा बनाए हुए थे। लोग औपचारिक व्यवस्था की कमियों की पूर्ति के लिए ट्यूशन और कोंचग पर अतिरिक्त खर्च भी करने को तैयार थे। यह सब इस तथ्य के बावजूद हो रहा था कि सबको पता था कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन और अध्यापक प्रशिक्षण आदि की कमजोरियां शिक्षा के आयोजन को अंदर से लगातार खोखला कर रही थीं। इस प्रणाली में परीक्षा की ही सबसे अधिक महत्ता है।

साल भर क्या पढ़ा-लिखा गया, इससे किसी को उतना मतलब नहीं होता जितना कि सालाना परीक्षा में कितने अंक या श्रेणी मिलती है? इसलिए सही-गलत किसी भी तरह परीक्षा में दांव लगाना ही सबका लक्ष्य होता गया। यह इसलिए भी कि परीक्षा

के अंक ही इस क्षणभंगुर जीवन में नित्य होते हैं। इनका ठप्पा अकाट्य होता है और विभिन्न अवसरों के लिए आर-पार तय करने वाला होता है। कहना न होगा कि परीक्षा की प्रामाणिकता को लेकर उच्च शिक्षा के शिखर तक संशय फैल चुका है। इस व्यवस्था से निकल रहे अधिकांश छात्र-छात्राओं की दक्षता, कौशल और योग्यता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बेरोजगार युवा वर्ग की बढ़ती संख्या स्वयं बहुत कुछ कहती है। इन खामियों से उबरने के लिए सरकार शिक्षा-नीति में बदलाव लाने की मुहिम पिछले पांच-छह वर्ष से चलती रही है और अब उसका खाका सार्वजनिक हो चुका है। जैसी सूचना है, उस खाके को मूर्त रूप देने का काम भी तेजी से चल रहा है, यद्यपि उसकी स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध नहीं है।

कोरोना महामारी ने शिक्षा को आपातकाल में डाल दिया है। साल भर से अधिक हुआ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सभी भौतिक दृष्टि से प्रत्यक्ष शिक्षा देने की जगह दूरस्थ शिक्षा का आश्रय लेने को मजबूर हैं। जहां सुविधा और संसाधन हैं, वहां इंटरनेट द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाने की कवायद और परीक्षा का कृत्य भी पूरा किया जा रहा है। विद्यार्थी और अध्यापक किसी को भी इसका अभ्यास न था। धीरे-धीरे जूम और ऐसे ही दूसरे प्लेटफार्म की सहायता से अध्यापन ने जोर पकड़ा, पर शिक्षा का व्यापक आशय मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ और स्वायत्त बनाना अब और दूर चला गया है। समता और समानता के लक्ष्य भी बिसराने लगे, क्योंकि बच्चे अच्छे मोबाइल और लैपटाप से लैस होना चाहते हैं, जो गरीब और निम्न मध्य वर्ग को सहजता से सुलभ नहीं हैं। इनकी आदत या व्यसन से पैदा होने वाले खतरे ऊपर से हैं। तथापि आज के हालात में हमारे पास इस अंधकार से उबरने का कोई और विकल्प भी नहीं है। कोरोना संक्रमण के भय से स्कूल कालेज को खोलना भी खतरे से खाली नहीं है। कोविड की तीसरी लहर का भी अंदेशा बना हुआ है, जिसका असर बच्चों और किशोरों पर अधिक होने के संकेत दिए जा रहे हैं।

लाखों अध्यापकों और करोड़ों विद्यार्थियों को लेकर चलने वाली देश की विराट शिक्षा व्यवस्था को स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रामाणिकता के साथ संचालित करना सचमुच एक बड़ी चुनौती है। इसलिए केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला किया। कई प्रदेशों के परीक्षा बोर्ड भी केंद्र की राह पर चल रहे हैं। सामान्य वार्षिक परीक्षा, जिसमें एक स्थान पर एक निश्चित समय में निश्चित प्रश्नों का उत्तर देना होता है, अभी तक मानक मानी जाती रही है।विद्यार्थियों, पालकों और अध्यापकों की सुरक्षा, सेहत और तनाव के मद्देनजर इस व्यवस्था को नकारना चुनौती और अवसर, दोनों है। विवश होकर ही सही अब इस अर्थहीन परीक्षा का उचित विकल्प ढूंढना ही होगा। सीखने का मूल्यांकन जैसा कि अभी तक ज्यादातर होता आया है, हौआ बन गया है। मूल्यांकन सीखने से बाहर की चीज नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मूल्यांकन से यह पता चलना चाहिए कि विद्यार्थी को क्या आता है? प्राप्तांक, ग्रेड और श्रेणी सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से ही यह बताते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से विद्यार्थी कहां खड़ा हुआ है, न कि कौशल की जानकारी देते हैं। परीक्षा में मिले अंकों से जीवन की वास्तविकताओं से टकराने और उनके समाधान के कौशल की कोई जानकारी नहीं मिलती है। वैसे भी साल भर या दो साल के शैक्षिक जीवन की यात्रा को दरकिनार रख तीन घंटे की परीक्षा में पांच-दस प्रश्नों के उत्तर से करियर का बनना-बिगड़ना श्रम की जगह भाग्य को ही महत्व देता है।

अब शिक्षाविदों को शैक्षिक योग्यता को दर्शाने वाले दूसरे मापकों की तलाश करनी होगी, जो न केवल अधिक साख वाले हों, बल्कि विद्यार्थियों की सृजनामक क्षमता, निर्णय की क्षमता और ज्ञान के उपयोग को दर्शाते हों। बौद्धिक योग्यता की प्रामाणिकता अपने परिवेश, समाज और प्रकृति के साथ रहने और अनुकूलन की व्यावहारिक उपलब्धि में ही प्रकट होती है। जो क्रियावान होता है, वही विद्वान होता है। इस दृष्टि से अब आभासी शिक्षण की दुनिया में रिमोट परीक्षा के एक सार्थक माडल को विकसित करना होगा, जिसमें स्मरण, समझ, विश्लेषण, सृजन और निर्णय आदि को सीखने के व्यापक परिवेश में स्थापित करना जरूरी होगा। इस दिशा में देश-विदेश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में प्रयोग चल रहे हैं। छात्रों को अपनी क्षमता व्यक्त करने का समुचित अवसर देना परीक्षा के भूत से मुक्ति दिलाने में निश्चित रूप से सहायक होगा, जो मानसिक रुग्णता और पारिवारिक तनाव का एक बड़ा कारण बना रहता है। परीक्षा का सार्थक विकल्प शिक्षा को उसकी अनेक बाधाओं से मुक्त करेगा।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

शिक्षा मंत्री के लौटने से 65 हजार पारा शिक्षकों में खुशी की लहर, ले सकते हैं बड़े फैसले

रांची । झारखंड की धरती पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के आगमन से 65 हजार पारा शिक्षकों में खुशी की लहर है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा लातेहार के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार, महासचिव अनूप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बेलाल अहमद ने खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद की है कि मंत्री 65 हजार पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की नियमावली पास कराकर सभी परिवारों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर देंगे। ज्ञात हो कि वो लंबे समय से कोरोना की बीमारी के कारण चेन्नई में इलाजरत थे। वे स्वस्थ होकर सोमवार को झारखंड लौटे हैं। उनके वापस आने पर जिले में कार्यरत 1520 पारा एवं प्रदेश में कार्यरत 65 हजार पारा शिक्षकों में खुशी का मौहाल है तथा सभी को पूरा विश्वास है कि मंत्री अपना वादा बहुत जल्द पूरा कर देंगे।

पारा शिक्षकों की बढ़ी उम्मीदें- इधर, मंत्री के झारखंड लौटने से पारा शिक्षकों को स्थायीकरण व वेतनमान की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मंत्री ने भी चेन्नई से दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा था कि झारखंड लौटने के बाद वे पारा शिक्षकों की समस्याओं को दूर करेंगे। बता दें कि जिस दिन पारा शिक्षकों के कल्याण कोष से संबंधित नियमावली पर स्वीकृति देने के लिए बैठक होनी थी, उसी दिन मंत्री की तबीयत बिगड़ गई थी तथा वे संक्रमित पाए गए थे। कोरोना को मात देकर चेन्नई से झारखंड लौटने के बाद मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि वे वहां लौटे हैं, जहां सबकुछ और सभी अपने हैं। इससे पहले उन्होंने रांची लौटने के लिए चार्टर्ड विमान पर बैठने के दौरान भी इसे लेकर ट्वीट किया था। रांची पहुंचने पर उन्होंने ट्वीट किया कि वे भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर, बिनोद बिहारी महतो की कर्मभूमि पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आशीष तले पहुंच गए हैं। उन्होंने राज्यवासियों को जोहार करते हुए कहा कि उनकी कामनाओं से ही वे स्वस्थ हो सके हैं। लंबे समय तक कोरोना संक्रमण से जूझनेवाले मंत्री ने कहा है कि लोगों को धैर्य नहीं खोना चाहिए। अंतिम वक्त तक लड़ने का जज्बा होना चाहिए।

बालिग हुए शरीर से जुड़े सोहणा-मोहणा, अद्भूत है पंजाब के दो अनोखे भाइयों की कहानी

अमृतसर । असंभव..। इस शब्द के आगे कई लोग लोग घुटने टेक देते हैं। असल में असंभव शब्द का मोल उस समय तक ही है जब तक इंसान हार न मान ले। परंतु, जो इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है वो मिसाल कायम कर देता है। ऐसी ही मिसाल के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जन्म के बाद पिंगलवाड़ा में पले और एक ही शरीर से जुड़े दो भाई सोहणा-मोहणा। अक्सर यही कहा जाता है कि शरीर से जुड़े ऐसे बच्चे ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहते, परंतु इन दोनों भाइयों ने सारे मिथक तोड़ दिए हैं। 14 जून, 2003 को दिल्ली के सुचेता कृपलानी अस्पताल में जन्मे सोहणा और मोहणा अब बालिग हो गए हैं। अब उन्हें वोट का अधिकार मिल जाएगा। दोनों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तीन वर्ष का डिप्लोमा भी कर लिया है। दोनों की जिंदगी आसान नहीं रही। वह छाती के नीचे से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के सिर, छाती, दिल, फेफड़े और रीढ़ अलग-अलग हैं लेकिन बाकी शरीर में किडनी, लीवर, और ब्लेडर सहित शरीर के अन्य सभी अंग एक ही व्यक्ति की तरह हैं। यह भी अदभुत है कि एक-दूसरे से जुड़े युवा हो चुके सरकारी दस्तावेज में अलग-अलग व्यक्ति हैं। दसवीं, 12वीं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की परीक्षा में उनके रोल नंबर अलग-अलग थे। आधार कार्ड भी अलग-अलग हैं। अब पिंगलवाड़ा सोसाइटी ने 14 जून को इनके 18 वर्ष के हो जाने पर वोट बनाने के लिए अलग-अलग आवेदन भी किया है। अमृतसर के एडीसी हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि जैसे इन दोनों के आधार कार्ड अलग-अलग हैं, उसी तरह दोनों के वोट भी अलग-अलग बनेंगे। विकृति के बावजूद सोहणा और मोहणा हर काम से पहले आपसी सामंजस्य बिठाते हैं। यदि सोहणा कहीं जाना चाहता है तो मोहणा को बता देता है। इससे उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होती है। इसका कारण यह है कि उनकी एक टांग सोहणा और दूसरी मोहणा के दिमाग से मिलने वाले निर्देश को मानती है। दोनों आपस में सामंजस्य बिठा लेते हैं और फिर दोनों का दिमाग एक तरफ चलने का निर्देश देता है तो दिक्कत नहीं आती। किसी विद्युत उपकरण की मरम्मत करनी दो तो सोहणा उपकरण पकड़ता है और मोहणा पेचकस या प्लास की मदद से उसे ठीक करता है।

एक रोता था तो दूसरा चुप करवाता था- डाक्टरों के अनुसार दो लाख में एक ऐसा केस होता है जब शरीर से जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं। सोहणा और मोहणा भी उन्हीं में से एक हैं। पिंगलवाड़ा की बीबी इंद्रजीत कौर ने बताया कि जब उन्हें यहां लाया गया तो वह दो माह के थे। दोनों की देखरेख के लिए नर्स रखी। दोनों ने पढ़ाई के साथ-साथ मानांवाला में कार्यरत इलेक्ट्रिशियन लखबीर सिंह से इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा और उसे अपना उस्ताद मानते हैं।

कांग्रेस ने कहा, शहर के स्लम एरिया, वार्ड और ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर बनाए जाएं नए वोट

जालंधर । पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवासी सेल के उपचेयरमैन रवि शंकर गुप्ता ने कहा कि शहर के स्लम एरिया में कैंप लगाकर नए मतपत्र (वोट) बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर चंद महीने शेष बचे हैं। इसके चलते राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी हैं। बावजूद इसके, अन्य राज्यों से आकर जिले में रहने वाले लाखों लोगों में से अधिकतर के वोट नहीं बन पाए हैं। उनके मतपत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

गुप्ता ने कहा, इस तरफ न तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही किसी ने इसे लेकर गंभीरता दिखाई है। ऐसे में ये लोग वोट के अभाव में भारतीय लोकतंत्र प्रणाली का हिस्सा बनने से वंचित रह जाएंगे। रवि शंकर गुप्ता ने कहा कि वोट का अधिकार देश के हर नागरिक को संविधान में दिया गया है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने से अधिकतर लोग मतदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को गंभीरता दिखाते हुए नए मतपत्र तैयार करने के लिए स्टाफ तैनात करना चाहिए। इसके लिए विधानसभा हलका वार्ड तथा ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जाने की जरूरत है।

धनबाद के अभिषेक सिंह बने भारत तिब्बत सहयोग मंच के युवा विभाग के मंत्री

धनबाद । भारत तिब्बत सहयोग मंच, युवा विभाग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा की गई। इसमें धनबाद के अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय मंत्री (सचिव) बनाया गया है। विगत 22 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में यह मंच संचालित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अभिषेक सिंह को संघ और सामाजिक कार्य में बेहतरीन कार्य के कारण यह जिम्मेदारी सौपी गई है। अभिषेक सिंह ने बताया कि वर्ष 1999 में धर्मगुरु दलाई लामा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पांचवें सर संघचालक केएस सुदर्शन के मार्गदर्शन में इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में मंच की स्थापना की गई। मंच के माध्यम से हमारा मुख्य कार्य चीन के नापाक मंसूबों के खिलाफ सरकार एवं देशवासियों को आग्रह करना है और बताना है कि चीन के पुराने रवैये को देखते हुए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश की बागडोर संभालने के पहले चीन आये दिन भारतीय सीमा में घुसपैठ करता रहता था। किसी को भनक तक नहीं लगती थी द्य उसका कारण सिर्फ यह था कि सरकार की ओर से घुसपैठ की खबरों को छिपाया जाता था। वर्तमान सरकार चीन को हर स्तर पर मुहतोड़ जवाब दे रही है। ऐसे में हम सभी मंच के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि चीन के नापाक मंसूबों के खिलाफ पूरे देश में जन जागरण अभियान को और तेज किया जाए। देशवासियों को यह बताएं कि चीन आर्थिक रूप से जितना कमजोर होगा, भारत उतना ही सशक्त होगा मंच के कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश- जुनून देखने को मिल रहा है, उससे बहुत ही शीघ्र तिब्बत की आजादी का मार्ग प्रशस्त होगा और हम सभी देशवासियों को बिना किसी रोक- टोक के अपने आराध्य देव भगवान भोले नाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा।

आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। यदि वह कुछ भी नापाक इरादे से करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। मंच के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं को जो अवसर प्राप्त हुआ है, यह हम सभी को भगवान भोलेनाथ की कृपा एवं आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है द्य इसे एक अवसर मानकर हम सभी राष्ट्र एवं समाज की सेवा में लगें। भगवान की कृपा से मंच अपने मिशन में जरूर कामयाब होगा। झारखंड प्रांत अग्रणी भूमिका में रहेगा और सभी कार्यकर्ता अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे।

सीएम योगी आदित्यनाथ का टीम-09 को निर्देश, कोरोना के थर्ड स्ट्रेन से निपटने की तैयारी में जी-जान से जुटें

लखनऊ । सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर टीम-09 के साथ समीक्षा बैठक की। प्रदेश में अब स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। इसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ रोज बैठक कर नए-नए निर्देश भी जारी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार अब कोरोना वायरस संक्रमण के थर्ड स्ट्रेन से निपटने की तैयारी में जुट गई है।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश अब सभी तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस संक्रमण की पहली लहर के दौर में हमारे पास संसाधनों की घोर अभाव था। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हमको पर्याप्त संसाधन मिले। हमारे पास अब पहले से काफी बेहतर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सेकेंड स्ट्रेन के कमजोर पडऩे के कारण हमको अभी भी सुस्त नहीं पडऩा है, हमको अभी भी काफी सजग रहना है। सभी जगह पर अपेक्षित चिकित्सा उपकरण का इंतजाम भी देखना है। थर्ड स्ट्रेन से भी हमें पहले की तरह ही बहादुरी से निपटना है। सभी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आइसीयू (पीकू) के कम से कम 50-50 बेड तैयार करें। इतना ही नहीं जिला चिकित्सालयों में भी इससे निपटने की तैयारी करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मेडिकल ऑक्सीजन जेनेरेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। बुधवार पांच और प्लांट की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में 441 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित की स्थापना की जा रही है। इनमें से लगातार प्रयासों से अब सौ ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। प्लांट स्थापना से जुड़े कार्यों की सतत समीक्षा की जाए। इस संबंध में भारत सरकार से समन्वय बनाए रखा जाए। अब 50 बेड से अधिक सभी अस्पताल ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिहाज से आत्मनिर्भर होंगी।

ट्रैक पर फोकस्ड वैक्सीनेशन- सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण की पहली डोज प्राप्त कर चुके लोगों की संख्या दो करोड़ से अधिक हो चुकी है, जबकि 39 लाख 11 हजार लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। 18 से 44 आयु वर्ग के 50 लाख 81 हजार युवाओं को वैक्सीन कवर मिल चुका है। 24 घंटों में 03 लाख 64 हजार 723 लोगों ने टीका-कवर प्राप्त किया। इस तरह अब तक 02 करोड़ 42 लाख 57 हजार से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है।

तेजी से पूरी करें मेडिकल कॉलेज में भवन निर्माण की प्रक्रिया- सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। गुणवत्ता और समयबद्धता पर फोकस रहे। नौ मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इन कार्यों को यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जाए। 14 अन्य प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से पठन-पाठन शुरू करने के लक्ष्य को देखते हुए आवश्यक तैयारियां समय से पूरी की जाएं।

निगरानी समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण- सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना प्रबंधन में निगरानी समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। गांवों में भ्रमण करते समय निगरानी समितियां यह भी सुनिश्चित करें कि कोई जरूरतममंद राशन से वंचित न रहे। हर गरीब, निराश्रित और अन्य पात्र लोगों को राशन जरूर मिले।

अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान का कार्यकाल बढ़ा, समर्थकों में खुशी

मुरादाबाद । राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान का कार्यकाल बढ़ा दिया है। उनका तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। कार्यकाल बढ़ाए जाने पर साध्वी ने प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद जताया। साध्वी को उनके समर्थकों ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया। अमरोहा के मंडी धनौरा में युवा राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगा। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। अमरोहा मार्ग पर बीएसडी कालेज में युवाओं को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। नौगांवा विधानसभा प्रभारी नितिन धारीवाल ने कहा कि रुहेलखंड क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में गांव गांव सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। आज भाजपा के राज में किसान, मजदूर व व्यापारी हर वर्ग का शोषण हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस मौके पर यशवीर खटाना, अनुज चौधरी, मनी धारीवाल, शुभम चड्ढा, हनी तोमर, रवि राठी आदि मौजूद थे। सम्भल के गुन्नौर के मुहल्ला फजैल में आए दिन बिजली हाईटेंशन की लाइन से घटनाएं होती रहती है। ऐसे में कांग्रेसियों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर बिजली की लाइन को मुहल्ले से हटवाने की मांग की। गुन्नौर के मुहल्ला फजैल में आबादी के बीच से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। लाइन नीचे होने के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। 14 जून को कस्बा का शफीक भी इसी लाइन की चपेट में आकर झुलस गया था। बुधवार को कांग्रेसियों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर मुहल्ले से लाइन हटवाने की मांग की है।

मोहाली में कोरोना के दौरान 108 एंबुलेंस सेवा से 44,000 से अधिक मरीजों को पहुंचाया अस्पताल

मोहाली । पंजाब में 108 एंबुलेंस आपातकालीन सेवाओं के तहत कोरोना महामारी के दौरान संबंधित विंग के पास लगभग 27,000 कॉल्स आई हैं। वहीं, मोहाली सेहत विभाग के मुताबिक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (ईएमएस) जोकि पंजाब में 108 एंबुलेंस आपातकालीन सेवाओं के लिए जिम्मेदारी निभा रही है मोहाली जिले में 44,000 से अधिक रोगियों की सफलतापूर्वक सेवा प्रदान कर अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक 1,500 से अधिक प्रोफेशनल्स ज की एक समर्पित स्टाफ ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक मामले को सभी पहलुओं में रिस्पॉन्स समय को कम करने के लिए अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया। जिससे एंबुलेंस की तत्काल आवश्यकता को पूरा करते हुए सिस्टम को और अधिक मजबूत और कुशल बनाया। प्रोजेक्ट हेड सैकत मुखर्जी, ने कहा कि 108 एंबुलेंस पंजाब के लोगों के लिए आपातकालीन में एंबुलेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड के दौरान मरीजों की आपातकालीन जरूरतों के लिए टीम 108 एंबुलेंस चौबीसों घंटे काम कर रही। मुखर्जी ने बताया कि इस काम में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों से सहायता दी जा रही है। जिससे क्षेत्र में एंबुलेंस सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल रही है।ध्यान रहे कि 2011 से राज्य में ये सेवा शुरू की गई थी। कोविड के दौरान 108 एंबुलेस सेवा के अलावा जो दूसरे लोग एंबुलेंस चलाते है ओवर प्राइजिंग की शिकायतों के बाद प्रशासन की ओर से एंबुलेंस चलाने के रेट फिक्स कर दिए गए थे। जिसमें प्रशासन की ओर से तीन अलग अलग केटगरिज में एंबुलेंस के रेट्स को विभाजित किया गया था। कोविड के मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए एंबुलेंस सेवा को प्रशासन ओर मजबूत करने की तैयारी में अभी से लग गया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में कथित अयोध्या भूमि खरीद घोटाले के मुद्दे के विरोध में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को हिरासत में लिया।

हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े की जांच जिले को सौंपने पर सवाल

देहरादून। हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना जांच में हुई गड़बड़ी को लेकर मामला अब तूल पकड़ गया है। प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद भी उच्च स्तरीय जांच के स्थान पर जिला स्तर पर जांच कराने का फैसला सवालों के घेरे में है। पूरे प्रकरण को लेकर अंगुलियां स्वास्थ्य विभाग और नौकरशाही पर भी उठ रही हैं। कारण, यह मामला उस समय का है, जब प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ ही था। तब सरकार का फोकस कुंभ के आयोजन पर था और नीतिगत निर्णय लेने में नौकरशाही के साथ विभाग की अहम भूमिका थी।

हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना जांच में गड़बड़ी का मामला छोटा नहीं है। देखा जाए तो शुरू से ही इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा उन्हें सौंपा गया, जो खुद जांच के दायरे में हैं। आलम यह है कि शासन द्वारा जिला स्तर पर सौंपी गई जांच भी दो स्तर पर हो रही है। एक जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित समिति कर रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी अलग जांच बिठा दी है। यहां सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रारंभिक जांच में ही बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ में आ गई थी, तो फिर मामले को हल्के में क्यों लिया गया। अमूमन होता यह है कि जब किसी प्रकरण की प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर हमेशा ही उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाती है। जांच का फलक व्यापक हो सके और निचले स्तर के अधिकारी जांच को प्रभावित न कर सकें। इस प्रकरण में इसके उलट हुआ। विडंबना यह कि जांच वही कर रहे हैं, जिन्होंने जांच एजेंसियों के लिए टेंडर आमंत्रित किए और जांच सुनिश्चित करने तथा इस पर नजर रखने के लिए मानक बनाए। दरअसल, कुंभ के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 22 निजी लैब को जांच के लिए अनुबंधित किया था। इनमें से नौ लैब को हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में जांच की जिम्मेदारी दी गई। इसमें प्रारंभिक तौर पर दो लैब की गड़बड़ी सामने आई है। इनमें एक लैब हरियाणा के हिसार की तो दूसरी दिल्ली की है।

जमीन विवाद पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज बोले- चंदा की रसीद दिखा पैसे वापस ले लें अखिलेश यादव व संजय सिंह

उन्नाव । रामनगरी अयोध्या में जमीन की खरीद पर चल रहे विवाद के प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज भी कूद पड़े हैं। उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबां में झांक लें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव या फिर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को अगर घोटाले का शक है तो दोनों नेताओं ने जो चंदा दिया है, उसको वापस ले लें। इसके लिए उनको चंदा देने वाली अपनी रसीद दिखानी पड़ेगी। उन्नाव में अपने आवास पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण में राम भक्तों का धन लग रहा है, उस पर सवाल उठाने का नहीं। मंदिर निर्माण के लिए जमीन के क्रय पर सवाल पर खड़े करने वालों से

मेरा अनुरोध है कि अगर उन्होंने चंदा दिया है तो वह लोग रसीद दिखाकर अपना धन वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीराम के मंदिर निर्माण में सारा धन राम भक्तों का लग रहा है, अखिलेश यादव या फिर संजय सिंह जैसे सवाल खड़े करने वालों का नहीं लग रहा है। सवाल उठाने वालों ने अगर मंदिर ट्रस्ट को चंदा दिया हो तो वह अपनी रसीद दिखाकर मुझसे उतनी धनराशि वापस ले जाएं। अगर चंदा नहीं दिया है तो फिर उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है।

सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि श्रीराम मंदिर के लिए जमीन क्रम पर सवाल खड़ा करने वाले वही लोग हैं, जिनके पुरखों ने कहा था कि वहां परिंदा पर नहीं मारने पाएगा। वहां पर एक ईंट नहीं रखने देंगे और रामभक्तों पर गोली चलवाई थी। अब मंदिर निर्माण शुरू होने से फिर पेट में दर्द होने लगा। जिस पार्टी के मुखिया ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी। वहां पर आज राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यह बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही है।

उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद पर सारे आरोप बेबुनियाद है। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने भगवान राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना सर्वथा निराधार है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है।

श्री पारस हास्पिटल प्रकरण में बयानों तक ही सिमट गई पुलिस की विवेचना, नहीं आया नतीजा सामने

आगरा । पारस हास्पिटल का वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज हुए मुकदमे की विवेचना बयानों तक ही सिमट कर रह गई है। अभी तक पुलिस तीस लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। मगर, आरोपित डाक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

श्री पारस हास्पिटल का एक वीडियो सात जून को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें हास्पिटल संचालक डा. अरिंजय जैन 26 अप्रैल को आक्सीजन की कमी और माकड्रिल करने की बात कहते हुए दिखे थे। वीडियो वायरल होने के बाद उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आरके अग्निहोत्री ने न्यू आगरा थाने में धारा 144 के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इंस्पेक्टर न्यू आगरा भूपेंद्र बालियान इसकी विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक इस मुकदमे में 30 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें वीडियो बनाने के समय डाक्टर के चैंबर में मौजूद लोग और डाक्टर के साथ कई अन्य लोग भी हैं। यह अभी तक 26 अप्रैल को हास्पिटल में मौजूद मरीजों के किसी तीमारदार से पुलिस ने बात नहीं की। उनके किसी के बयान दर्ज नहीं किए हैं। पुलिस मूल वीडियो की तलाश भी कर रही है, लेकिन यह वीडियो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है।

पशुपति पारस का निर्विरोध एलजेपी अध्यक्ष निर्वाचित होना तय, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में चिराग पासवन

पटना । लोक जनशक्ति पार्टी में विरासत की जंग और तेज हो गई है। आज पारस समर्थक पटना में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। चुनाव में अकेला प्रत्याशी होने के कारण पारस का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होना तय है। इसके बाद पारस गुट चुनाव आयोग के समक्ष असली एलजेपी होने का दावा करेगा। अध्यक्ष के चुनाव के बाद पशुपति पारस और समर्थक सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने भी जा सकते हैं। आज हीं पारस उन आरोपों के जवाब भी देंगे, जो चिराग पासवान ने लगाए हैं। इस बीच चिराग पासवान दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। साथ ही और बागियों को भी बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। पारस को संसदीय दल का नेता बनाने का विरोध करते हुए चिराग पासवान पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख चुके हैं।

एलजेपी सांसद सूरजभान के आवास पर आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हो रही है। इमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है। इसके लिए पशुपति पारस अकेले उम्मीदवार हैं। ऐसे में पशुपति पारस का अध्यक्ष बनना तय है। शाम पांच बजे के पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी जाएगी। सूरजभान सिंह के भाई व सांसद चंदन सिंह ने कहा है कि आज ही पशुपर्ता पारस पार्टी की कमान संभाल लेंगे। जैसे हर पार्टी का नेतृत्व बदलता है, उसी तरह एलजेपी में भी हो रहा है। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पशुपति पारस देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें अपना समर्थन दे सकते हैं। हालांकि, बिहार विधानसभा में एलजेपी का एक भी विधायक नहीं रहने के कारण इस समर्थन का केवल संकेतिक अर्थ ही होगा। पशुपति पारस अध्यक्ष चुने जाने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात भी रखेंगे।

इस दौरान वे चिराग पासवान के लगाए आरोपों का जवाब देने के क्रम में उनपर जमकर बरसेंगे, यह तय है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि वहां चिराग पासवान कानून विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वे पार्टी पर अपने दावे को लेकर तथा बागियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। साथ ही खुद को पार्टी का अध्यक्ष बताते हुए कुछ और बागियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं।

चिराग ने लिखा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र- इसके पहले चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता मनोनीत करने पर विरोध जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह नियम के खिलाफ है। पार्टी के संविधान के अनुच्छेद-26 के मुताबिक, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही यह तय करने के लिए अधिकृत है कि लोकसभा में पार्टी का नेता कौन होगा। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है और कहा है कि वे लोकसभा में एलजेपी के नेता के तौर पर उन्हें मान्यता देने से संबंधित सर्कुलर जारी करें।

चिराग पासवान समर्थकों ने लोक जनशक्ति पार्टी के पांच सांसदों का किया पुतला दहन

टिकारी (गया) । लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) में विरासत की जंग और तेज हो गई है। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। बुधवार को पटना से लेकर दिल्ली तक पारस-चिराग के समर्थकों ने हंगामा बरपाया। पारस के समर्थकों ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कब्जा जमा लिया और चिराग से जुड़े पोस्टर-बैनर का फाड़ दिया। इतना ही नहीं, समर्थकों ने पारस के संसदीय दल के नेता चुने जाने पर बधाई का बड़ा बैनर लोजपा के गेट पर लगा दिया। इसके पहले चिराग समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में पांचों बागी सांसदों के फोटो पर कालिख पोत दी थी। वहीं, दिल्ली में पारस के सरकारी आवास पर चिराग के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए हंगामा मचाया। गया के टिकारी में भी चिराग के समर्थकों ने पांचों बागी सांसदों का बुधवार को पुतला दहन किया गया। पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार पासवान के नेतृत्व में कॉलेज मोड़ से पार्टी कार्यकर्ता जुलूस निकालकर पंचानपुर पहुंचे। वहां अंबेडकर चौक पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने पशुपति कुमार पारस के साथ पार्टी से बगावत कर अलग हुए सांसदों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए एक-एक कर पांचों सांसदों का पुतला दहन कर दिया।

सूरजभान के आवास पर राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक - आज गुरुवार को लोजपा में तीन महत्वपूर्ण गतिविधियां होंगी। चुनाव अधिकारी सूरजभान सिंह के पटना स्थित आवास पर पूर्वाह्न 11 बजे बागी खेमे की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होनी है। इसमें बागी गुट अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगा। पशुपति कुमार पारस ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया पांच दिनों के भीतर पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा।इसकी तैयारियों को लेकर पशुपति कुमार पारस अपने सहयोगी सूरजभान सिंह, सांसद चंदन सिंह एवं प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल समेत अन्य नेताओं के साथ एक ही प्लेन से बुधवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। हालांकि, प्रिंस राज साथ नहीं आए हैं। वे आज पटना पहुंचेंगे। सांसद वीणा देवी और महबूब अली कैसर मंगलवार की शाम को ही पटना आ चुके हैं।

उधर, लोजपा पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे चिराग पासवान बुधवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। चाचा पशुपति कुमार पारस पर पार्टी और परिवार को तोडऩे का आरोप लगाया। कहा कि चाचा के धोखे से हम अनाथ हो गए। बुधवार को चिराग दिल्ली स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुझे हटा दिया गया है, लेकिन पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष को पद से तभी हटाया जा सकता है, जब कि उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वह इस्तीफा दे दे। अभी मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए मैं ही लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इस पद से मुझे हटाया नहीं जा सकता है।

संसदीय दल का नेता बनाए जाने का विरोध- चिराग ने संसदीय दल के नेता पद से हटाने को भी असंवैधानिक बताया और कहा कि लोकसभा में पार्टी नेता की नियुक्ति का फैसला संसदीय समिति करती है, नहीं कि निर्वाचित सांसद।

कोलकाता में रात भर हुई भारी बारिश के बाद जलभराव वाले बाजार क्षेत्र में फल विक्रेता ग्राहकों का इंतजार करते हुए।

वन अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कोच्चि में एमाकुलम के कुट्टमपुझा इलाके के पास एक कुएं में गिरे एक हाथी को बचाया।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए।

एक नजर

पालघर की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद लगी भीषण आग, 5 लोग झुलसे

मुंबई । महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहाणू में वीरवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल के कई वाहन मौके पर पहुंच गए। पालघर जिला कलेक्टर कार्यालय का कहना है कि इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया करवा दिया गया है। फायर वर्क्स नाम की इस पटाखा फैक्ट्री में आग लगते ही हडकंप मच गया। विस्फोट के बाद लगी भयंकर आग से करीब 10 से 12 किलोमीटर तक के इलाके में मौजूद घरों को काफी नुकसान हुआ है। ये फैक्ट्री दहाणू हाईवे से करीब 15 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है। इस घटना में पांच लोग बुरी तरह झुलस गए हैं जिसमें से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पांचों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना भयंकर था कि उसकी आवाज 15 से 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और देखते ही देखते धुएं के गुबार ने पूरे आसमान को ढक लिया। हालांकि आग लगने के स्पष्ट कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद दमकल वाहन आग बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं।

मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआइए ने किया गिरफ्तार

मुंबई । राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप शर्मा के उपनगरीय अंधेरी स्थित आवास पर एंटीलिया बम मामले और मनसुख हिरेन की हत्या की जांच के सिलसिले में सुबह एनआइए ने छापा मारा था। अधिकारी ने बताया कि एनआइए की एक टीम ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ अंधेरी पश्चिम के जेबी नगर स्थित शर्मा के घर पर सुबह करीब छह बजे छापा मारा, उनसे केस के बारे में पूछताछ की जा रही थी। छापेमारी की सूचना मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने भी अपने जवानों को भी मौके पर तैनात कर दिया गया था। बता दें कि इससे पहले, प्रदीप शर्मा से एनआइए ने जांच के सिलसिले में दक्षिण मुंबई में अपने कार्यालय में दो दिनों तक पूछताछ की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे पहले पूर्व पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे, रियाजुद्दीन काजी, सुनील माने, पूर्व पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर को मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस सिलसिले में हाल ही में संतोष शेलार और आनंद जाधव को भी गिरफ्तार किया गया था। एनआइए का कहना था कि ये दोनों कथित तौर पर उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों वाली एसयूवी लगाने की साजिश में शामिल थे।

क्या है मामला – इस साल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास एक एसयूवी गाड़ी लावारिस हालत में मिली थी। ये गाड़ी बिजनेस मैन मनसुख हिरेन की बतायी जा गई थी। मनसुख हिरेन 5 मार्च को मुंब्रा में मृत अवस्था में पाए गए थे। इन दोनों मामलों की जांच पहले महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी, बाद में इसे एनआइए को दे दिया गया था।

गौरतलब है कि एंटीलिया केस में भी पूर्व पुलिसकर्मी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का नाम आया था और जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उनसे पूछताछ की थी। दरअसल एंटीलिया केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी। एटीएस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मनसुख हिरेन ने अंधेरी ईस्ट से ही अंतिम कॉल की थी और प्रदीप शर्मा का आवास अंधरी ईस्ट में ही है। इसी कारण प्रदीप शर्मा एटीएस और एनआइए के शक के घेरे में थे।एनकांउटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ज्ञात हो कि एनकांउटर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले प्रदीप शर्मा ने 2019 में विधानसभा चुनावों में शिवसेना में शामिल हुए थे। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाये। अब तक प्रदीप शर्मा 100 से भी यादा एनकाउंट कर चुके हैं, उन्हें फर्जी एनकाउंटर मामले में जेल की सजा भी हो चुकी है।

आसाराम बापू के कब्जे से मुक्त करवायी गई 55 करोड़ की जमीन, कर रखा था अवैध कब्जा

अहमदाबाद । अहमदाबाद महानगर पालिका ने आसाराम बापू के कब्जे से 55 करोड़ रुपये की 5000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया है। महानगर पालिका के वेस्ट जोन के टीडीओ ने मोटेरा में इस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। टीपी 21 के प्लॉट नंबर 412 की 5490 वर्ग मीटर भूमि आसाराम आश्रम ने कब्जा लिया था। इस जमीन की बाजार कीमत 55 करोड़ रुपए आंकी गई है। आसाराम के मोटेरा आश्रम के पास स्थित इस जमीन पर आश्रम वासियों ने अवैध कब्जा जमा लिया था। आश्रम परिसर को बढ़ाकर अहमदाबाद महानगर पालिका कि इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। गुजरात हाईकोर्ट की ओर से हाल ही राय सरकार को सरकारी संपत्तियों को खाली कराने का निर्देश जारी किया गया था। महानगर पालिका आसाराम के कब्जे वाली जमीन को खाली कराकर सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा है। महानगर पालिका ने पहले से इस जमीन को सार्वजनिक बाग-बगीचे अथवा खेल मैदान के लिए रखा था जिसे आसाराम आश्रम में कब्जा लिया गया था। इसके अलावा टीपी 46 के प्लॉट नंबर 217 पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने झोपड़े बना लिए थे। अधिकारियों ने इन अवैध झौंपड़ों को बुलडोजर चलाकर साफ करवा दिया था। इस सरकारी जमीन पर माफियाओं ने झोपड़े बनाकर उनके बीच रेती-बजरी का गोदाम बना लिया था।

गुजरात में बीते 24 घंटे 298 नए मामले, 5 संक्रमितों की मौत

अहमदाबाद । गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले अब पूरी तरह घट चुके हैं 7 जिलों में एक भी केस दर्ज नहीं किया गया जबकि आधा दर्जन जिलों में संक्रमण के 1-1 मामले सामने आए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 298 मामले सामने आए जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद महानगर पालिका में संक्रमण के 46 केस आए तथा 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अरवल्ली अमरेली तथा सूरत जिले में कोरोना से एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। इनके अलावा किसी भी जिले अथवा महानगर पालिका में कोरोना से मौत दर्ज नहीं हुई। गुजरात में एक्टिव केस की संख्या 8242 है जबकि पिछले 24 घंटे में 935 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे। मजे में अब तक 8 लाख 21376 लोग संक्रमित हुए जिनमें से 8 लाख 3122 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच गए। बीते 24 घंटे में राय में 2 लाख 18062 टीके लगाए गए राय में अब तक दो करोड़ 10 लाख 39 हजार 116 टीके लगाए जा चुके हैं। सूरत महानगर पालिका में 47 के स दर्ज हुई वडोदरा में 25, राजकोट 19, जामनगर 7, गांधीनगर 4, जूनागढ़ में 3, तथा भावनगर महानगर पालिका में एक केस दर्ज हुआ।

आनलाइन ठगी कर ऐश की जिंदगी जी रहा था आरोपित, नाइजीरिया में भी खरीदी चार करोड़ की संपति

ग्वालियर ,(एजेंसी)।

वैवाहिक विज्ञापन वेबसाइट जीवनसाथी डाट काम के जरिये संपर्क बनाकर युवती से चार लाख 85 हजार रुपये ठगने वाले नाइजीरिया के युवक जॉन जुलिओस ने भारत में ठगी कर जो पैसा कमाया, उससे नाइजीरिया में उसने चार करोड़ रुपये कीमत के फ्लैट खरीदे हैं। उसने दिल्ली व नोएडा में दो डुप्लैक्स व पत्नी के लिए बीएमडब्ल्यू कार व इको स्पो?र्ट्स कार भी खरीदी हैं। उसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल में स्थित भिंड की पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में यह स्वीकारा है। एक महीने में आरोपित के खाते में एक करोड़ 89 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। गौरतलब है कि भिंड पुलिस ने आरोपित जॉन को उत्तर प्रदेश के नोएडा से बीते दिनों पकड़ा है।

भिंड पुलिस के मुताबिक नाइजीरिया के इकोई लोगस का निवासी जॉन जुलिओस 2013 में भारत आया था। वह नोएडा स्थित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से फार्मेसी से स्नातक करना चाहता था। यहां आकर वह नाइजीरियन युवकों के साथ रहने लगा तथा उनके साथ मिलकर भारतीयों से आनलाइन ठगी करने लगा। जॉन के पास से पुलिस को फर्जी पासपोर्ट व कई एटीएम कार्ड, सिम कार्ड मिले हैं। भिंड डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा के मुताबिक, आरोपित करोड़ों रुपये की आनलाइन ठगी कर चुका है। ठगी के लिए एक सिम का एक ही बार उपयोग करता था। दिल्ली व नोएडा में खुद के डुप्लैक्स व फ्लैट होने के बावजूद पहचान छिपाने के लिए वह किराये के लग्जरी फ्लैट में रहता था। वह चार साल से ठगी कर रहा था। भिंड पुलिस को उसके पास से 18 मोबाइल मिले हैं। इनमें वह अब तक 2169 सिम कार्ड का उपयोग कर चुका है।

उसने अब तक इतनी ठगी की है कि उसे खुद याद नहीं कि भारत में उसने कितने लोगों को शिकार बनाया। पुलिस ने जीवनसाथी डाट काम को भी नोटिस दिया है। उनसे अकाउंट पर पंजीयन के दौरान सुरक्षा उपायों की जानकारी मांगी गई है।

10 दिन में 31 ठिकानों पर छापे, हर पता फर्जी– आरोपितों को पकड़ने के लिए पुलिस ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में 31 ठिकानों पर दबिश दी है। पुलिस जिस ठिकाने पर जाती, उसका पता फर्जी निकलता। आरोपित इतना शातिर है कि अपने घर का पता किसी को नहीं देता था। आनलाइन शापिंग में भी सतर्कता बरतते हुए सामान डिलीवरी के लिए अपने घर के बजाय पड़ोस का पता देता था। गौरतलब है कि इसके गिरोह में उत्तर प्रदेश के ओरैया जिले के भी कुछ आरोपित शामिल हैं।

दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार खोलने जा रही अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, इलाज और शिक्षा के साथ मिलेंगी सभी सुविधाएं

नई दिल्ली । कुछ बच्चों में देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ उनमें चलने, बोलने या सुनने समेत मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे विशेष बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने सात राष्ट्रीय संस्थानों और सात समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले हैं, जिनका गुरुवार को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इन सेंटर्स पर दिव्यांग बच्चों का इलाज किया जाएगा। बता दें कि कुछ बच्चों में जन्म के बाद बोलने, सुनने, चलने समेत कई तरह के मानसिक विकास जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता है।

ऐसे बच्चे तीन से 10 फीसद ही होते हैं। कुछ नवजात बच्चों में चिकित्सीय जांच के बाद ही इसका पता चल जाता है लेकिन ज्यादातर में माता-पिता को बच्चों की उम्र बढ़ने के बाद ही इस स्थिति की जानकारी हो पाती है। ऐसे में प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों में बच्चों के इलाज में काफी खर्च आता है और हर कोई इलाज एवं प्रशिक्षण का खर्च वहन नहीं कर पाता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में 14 क्रॉस-डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले हैं, जो सात राष्ट्रीय संस्थानों और सात समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में स्थित हैं। केंद्रीय मंत्री आज इनका उद्घाटन करेंगे।

वर्तमान में दिव्यांग बच्चों (0-6 वर्ष) या जिन बच्चों में विकास देरी से होता है, उनकी पुनर्वास देखभाल और इलाज के लिए डीईपीडब्ल्यूडी ने पायलट आधार पर 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करने की पहल की है। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, देहरादून, सिकंदराबाद, कोलकाता, कटक और चेन्नई में सात राष्ट्रीय संस्थानों और सुंदरनगर, लखनऊ, भोपाल, राजनांदगांव, पटना, नेल्लोर और कोझीकोड में सात समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में सेंटर्स खोले जा रहे हैं। ये 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सीय, पुनर्वास देखभाल सेवाओं और प्री-स्कूल प्रशिक्षण (0-6 वर्ष) के लिए निकटवर्ती सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल सभी प्रकार की अक्षमताएं शामिल हैं।

पुणे के इस स्टार्ट-अप ने तैयार किया पर्यावरण के अनुकूल हैंड सैनिटाइजर, हाथों को रखेगा मुलायम

मुंबई । जल्द ही बाजार में एक ऐसा सैनिटाइजर उपल्बध होगा जो हाथों को बेहद मुलायम बना कर रखेगा और लंबे समय तक चलेगा। दरअसल, पुणे में स्थित एक स्टार्ट-अप इस प्रकार के नए सैनिटाइजर को बाजार में लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह पर्यावरण के अनुकूल हैंड सैनिटाइजर होगा, जो हाथों की कोमलता को बरकरार रखेगा और जल्द उन्हें सुखाने का कार्य करेगा। अल्कोहल मुक्त इस सैनिटाइजर को सिल्वर नैनोपार्टिकल्स एक स्टार्ट-अप द्वारा विकसित किया गया है। बता दें कि वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले हैंड सैनिटाइजर को हाथों में लगाने के बाद जल्दी सूखाने की भी चुनौती है, जिसका सामना अभी तक लोग कर रहे हैं।

बार-बार सैनिटाइजर के उपयोग की आवश्यकता होगी कम– वेनोवेट बायोसॉल्यूशन द्वारा विकसित हैंड सैनिटाइजर रोगाणुरोधी गतिविधि को बढ़ाता है। जिसके तहत बार-बार सैनिटाइजर के उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा इस हैंड सैनिटाइजर के लिए क्लिनिकल परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस दौरान यह सैनिटाइजर वायरस को मारने में सफल साबित हुआ है। बता दें कि WeinnovateBiosolutions को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड के CAWACH 2020 द्वारा सहयोग मिला है। इसके जरिए कोलाइडल सिल्वर सॉल्यूशन आधारित हैंड सैनिटाइजर विकसित किया गया।

आत्मनिर्भर राष्ट्र को बनाने में मिलेगा सहयोग– वेनोवेट बायोसॉल्यूशन के.को.फाउंडर और सीओओ,डॉ अनुपमा इंजीनियर ने बताया कि अध्ययन के परिणामों के हैंड सैनिटाइजर के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का इंताजर हैं। उन्होंने आगे कहा कि,हमें यकीन है कि इस तरह के इनोवेशन से भारत को अपने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा और भविष्य में इस तरह की महामारियों का सामना करने के लिए एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करेगा।

तमिलनाडु में अब शेर की भी कोविड-19 से मौत, पहले एक शेरनी की भी जा चुकी है जान

चेन्नई । तमिलनाडु के एक जैविक उद्यान में बुधवार को 12 वर्षीय शेर की भी कोविड-19 से मौत हो गई। शेर को वंदालूर स्थित अरिगनार अन्ना जैविक उद्यान (एएजेडपी) के सफारी क्षेत्र में रखा गया था। इससे पहले यहां एक शेरनी की भी इसी बीमारी से मौत हो चुकी है। उद्यान के उप निदेशक ने एक बयान में बताया कि कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद शेर का सघन उपचार किया जा रहा था। तीन जून को भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ने एएजेडपी को भेजी गई रिपोर्ट में बताया था कि शेर कोरोना संक्रमित पाया गया है। उसी दिन नौ साल की एक शेरनी की कोरोना से मौत हो गई थी। जैविक उद्यान में मौजूद 14 में से सात शेर संक्रमित पाए गए थे। अधिकारियों ने कहा था कि तीन शेरों पर इलाज का असर कम हो रहा है। हालांकि, उद्यान के पशु चिकित्सकों और तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा उन्हें स्वस्थ करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रबंधन बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

अगले तीन दिनों में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीके की 56 लाख से अधिक डोज उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले तीन दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 56 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक उपलब्ध कराएगी। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि वैक्सीन 56,70,350 से अधिक खुराक पाइपलाइन में हैं और अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इसे प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल कोरोना वैक्सीन की दो करोड़ 18 लाख 28 हजार 483 खुराक अभी भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है।

मंत्रालय ने बयान में यह भी बताया कि भारत सरकार (मुफ्त चैनल) के माध्यम से और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27.28 करोड़ (27,28,31,900) से अधिक वैक्सीन की खुराक प्रदान की

जा चुकी है। आज सुबह 8 बजे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसमें से कुल 25,10,03,417 खुराक की खपत हो चुकी है। इसमें बर्बाद डोज भी शामिल है। 2.18 करोड़ (2,18,28,483) से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बताया कि राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 26.55 करोड़ (26,55,19,251) खुराक दी जा चुकी है। बता दें कि भारत ने इस साल 16 जनवरी को चरणबद्ध तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। इसमें स्वास्थ्यकर्मियों को सबसे पहले टीका लगाया गया। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 2 फरवरी को शुरू हुआ।

कोविड -19 टीकाकरण का अगला चरण 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू हुआ। भारत ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण 1 मई को 18-44 आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए शुरू किया गया था। भारत में तीन टीकों कोविशील्ड, कोवैक्सीन स्पुतनिक वी का इस्तेमाल हो रहा है।

अब भारत में गूगल लगाएगा 80 ऑक्सीजन प्लांट, 113 करोड़ रुपये देने का किया एलान

नई दिल्ली । अब भारत में गूगल 80 ऑक्सीजन प्लांट की मदद के लिए सामने आया है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गूगल ने आज बताया कि उसकी परोपकार शाखा गूगल डॉट ऑर्ग विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर देश में 80 ऑक्सीजन प्लांटों की खरीद और स्थापना करेगा। विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के कौशल विकास में मदद के लिए कंपनी 113 करोड़ रुपये (1.55 करोड़ डॉलर) का अनुदान देगी।

बता दें कि गूगल डॉट ऑर्ग अपने इस एलान के तहत 80 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए गिवइंडिया को करीब 90 करोड़ रुपये और पाथ को करीब 18.5 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए अपोलो मेडस्किल्स के जरिए कोरोना प्रबंधन में 20,000 अग्रणी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए गूगल डॉट ऑर्ग भारत के 15 राज्यों में 180,000 आशा कार्यकर्ताओं और 40,000 एएनएम के कौशल विकास के लिए 3.6 करोड़ रुपये (पांच लाख अमरीकी डॉलर) का अनुदान अरमान को प्रदान करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल द्वारा अरमान को दिए गए इस अनुदान के इस्तेमाल से आशा और एएनएम को अतिरिक्त सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। गूगल इंडिया के कंट्री हेड और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि गूगल में लोगों के पास सुरक्षित रहने के लिए जरूरी जानकारी और उपकरण होने चाहिए।

ऐसा क्या हुआ कि उदयपुर के एक बड़े निजी अस्पताल में मरीजों का उपचार पर लगी रोक, रजिस्ट्रेशन किया निरस्त

उदयपुर। जिला प्रशासन ने उदयपुर के एक बड़े निजी क्षेत्र के अस्पताल पर क्लिनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया अब इस अस्पताल में मरीजों का उपचार नहीं हो पाएगा। यही नहीं अस्पताल प्रबंधन पर भर्ती मरीजों को पर्याप्त चिकित्सकीय उपलब्धता नही करवा पाने, इलाज के दौरान लापरवाही बरतने एवं मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यहां उदयपुर-नाथद्वारा रोड स्थित शर्मा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर बुधवार शाम जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग का बेड़ा पुलिस जाब्ते के साथ आया और अस्पताल को सीज कर दिया गया। इससे पहले वहां भर्ती मरीजों को शहर के दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। एक के बाद कई एम्बुलेंसों को देखकर मार्ग से गुजर रहे व्यक्ति किसी अनहोनी की आशंका से वहां ठहर गए। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। हालांकि बाद में लोगों को पता चला कि अस्पताल का पंजीयन जिला प्रशासन ने रद्द करते हुए यहां मरीजों के उपचार पर पूरी तरह रोक लगा दी है। मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराड़ी, गिर्वा उपखंड अधिकारी अपर्णा गुप्ता, तहसीलदार हिम्मत सिंह राव, सुखेर थानाधिकारी रोशन लाल भी मौजूद थे।

सीएमएचओ डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया कि क्लिनिकल एक्ट के तहत यह कार्रवई की गई है। अस्पताल में दर्शाए गई बेड क्षमता, चिकित्सकों की उपलब्धता एवं अन्य तथ्यों की जाँच के लिए जिला कलेक्टर द्वारा जाँच दल गठित किया गया था। जाँच रिपोर्ट में उक्त अस्पताल में चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति से लेकर अन्य कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई ।

बेरोजगारी का दंश झेल रहे टेंट व्यवसायियों को सरकार से राहत का है इंतजार

जोधपुर । कोरोना केस काल में मॉडिफाई लॉकडाउन के बाद भी विवाह समारोह या अन्य आयोजनों से जुड़े व्यवसाय मायूस है और बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। त्रिस्तरीय लॉकडाउन के बाद मॉडिफाई अनलॉक शुरू तो हुआ है लेकिन टेंट व्यवसाई और ऐसे ही विवाह सरीखे अन्य आयोजनों से जुड़े व्यवसायियों को सरकार से नाराजगी है। जिसकी वजह सरकारी गाइडलाइन में लगातार टेंट, लाइट, कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी गई है ऐसे में राज्य का व्यवसाय अन्य राज्यों में स्थानांतरित होना और व्यवसाय से जुड़े प्रदेश के तमाम व्यापारियों और लेबर के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो रहा है।

जोधपुर में संगठन के महासचिव शिवकुमार भाटी ने बताया कि सरकार द्वारा 31 मई 2021 को जारी गाइडलाइन में विवाह के आयोजन को 30 जुन 2021 तक बन्द रखा गया है, जबकि टेन्ट एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास स्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जसमा क्षेत्र के विधायक एवं समस्त राजस्थान के 25 सांसदों को मेल भेज कर ज्ञापन दिया गया था व समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने विवाह समारोह अन्य व्यवसाय पर 30 जून तक रोक लगाई थी। लेकिन अब सरकार ने अन्य व्यवसायियों को रियायत दी है, ऐसे में टेन्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी राहत प्रदान की जाए।

संगठन के सुनील भाटी के अनुसार विवाह समारोह या अन्य समारोह जुड़े व्यवसाय टेंट और लाइट डेकोरेशन को कोई राहत प्रदान नहीं की गई। सरकार द्वारा सिटी बसों व रोडवेज का संचालन शुरू किया जा चुका है ऐसे में विवाह समारोह में तोरण गेट लगना और वर द्वारा घोड़ी पर बैठ कर तोरण मारना धर्म के अनुसार होता है परन्तु सरकार ने सभी पर पाबन्दी लगा दी ,जो तर्कसंगत नहीं है।

प्रदेश भर में सालाना 10000 करोड रुपए का व्यवसाय करने वाले और समाज के सुख दुख में बराबर के भागीदार कहे जाने वाले टेंट व्यवसाय दोहरी मार झेल रहे हैं। जोधपुर में संघटन के अध्यक्ष जितेन्द्र फोफलिया ने बताया कि मैरिज गार्डन संचालन करने वाले लोगों ने अपने सभी टैक्स और स्थानीय निकायों में लगने वाले करों की राशि जमा करा दी है इसके बावजूद सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदी के बाद किसी प्रकार की रियायत नहीं मिली है जबकि सरकार द्वारा विवाह समारोह को लेकर पूर्व में बुक की गई अग्रिम राशि लौटाने को लेकर दबाव बनाया गया है। जोधपुर टेन्ट ऐसोसिएशन ,राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति जयपुर, ने बुकिंग की अग्रीम राशि लौटाने के विषय को लेकर टेन्ट प्रतिनिधियों ने सरकार तथा सरकार के प्रत्येक विधायक से संपर्क करके अपनी समस्या बताई गई थी। इसके अलावा राजस्थान के 25 सांसदों से भी संगठन के पदाधिकारियों ने संपर्क किया था। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल दिखाई नहीं दे रही है ऐसे में भवन और गार्डन प्लेस मेंटिनेंस ,उनके लिए की गई आवश्यक साज सज्जा और लेबर का भार टेंट संचालकों और मैरिज प्लेस संचालकों को उठाना पड़ रहा है।

प्रदेश के टेंट व्यवसाईयो ने राजस्थान की सरकार से धार्मिक सांस्कृतिक और विवाह जैसे आयोजनों पर लगी रोक को हटाने और विवाह आयोजनों में सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 200 किए जाने की मांग की है। जिससे कि मंदी की मार झेल रहे इस व्यवसाय को राहत मिल सके, साथ ही प्रदेश से पलायन कर रहे विवाह आयोजनों को रोका जा सके। विवाह आयोजनों से जुड़े अन्य व्यवसायियों को भी काम कर अपनी आजीविका चलाने का अवसर मिल सके। टेंट व्यवसाइयों ने सरकार से मांग किसान क्रेडिट कार्ड के जैसे टेन्ट कार्ड जारी किए जाए और आर्थिक मदद देने की मांग की है।

सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इमोशनल हुईं सारा अली खान

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें परिवार और फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्रिटीज भी याद करते दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने सोशल एकाउंट पर सुशांत से जुड़ी यादें, तस्वीरें और वीडियोज शेयर करते हुए भावुक पोस्ट किया है। वहीं इस बीच हाल ही में सारा अली खान का एक पोस्ट भी चर्चा में आ गया है। उन्होंने सुशांत को याद करते हुए एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। जिसमें वो अपनी जिंदगी में सुशांत की अहमियत बताती दिख रही हैं। सारा ने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें सुशांत, एक्ट्रेस के साथ पूल में देते दिखाई दे रहे हैं।

केदारनाथ की दिलाई याद

सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें दोनों एक पूल में नजर आ रहे हैं। दोनों के मुस्कुराते चेहरे फिल्म 'केदारनाथ' की याद दिला रह हैं। ये सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी, जिसमें उन्होंने सुशांत के साथ काम किया था। सारा के इस पोस्ट पर सुशांत के फैंस की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लोग उन्हें याद करते हुए इमोशनल नजर आ रहे हैं।

'आज भी विश्वास नहीं होता'

इस फोटो के साथ दिए कैप्शन में सारा ने लिखा- 'जब भी मुझे मदद, सलाह और हंसने की जरूरत पड़ी तो तुम हमेशा मेरे साथ थे। तुमने मुझे एक्टिंग की दुनिया से मिलवाया। मुझे यकीन दिलवाया कि सपने सच हो सकते हैं और मुझे वो सबकुछ दिया जो आज मेरे पास है। आज भी विश्वास नहीं होता कि तुम चले गए हो। लेकिन जब भी मैं सितारों, उगते हुए सूरज और चांद को देखती हूं तो मुझे एहसास होता है कि तुम यहीं हो। केदारनाथ से एंड्रोमेडा तक'।

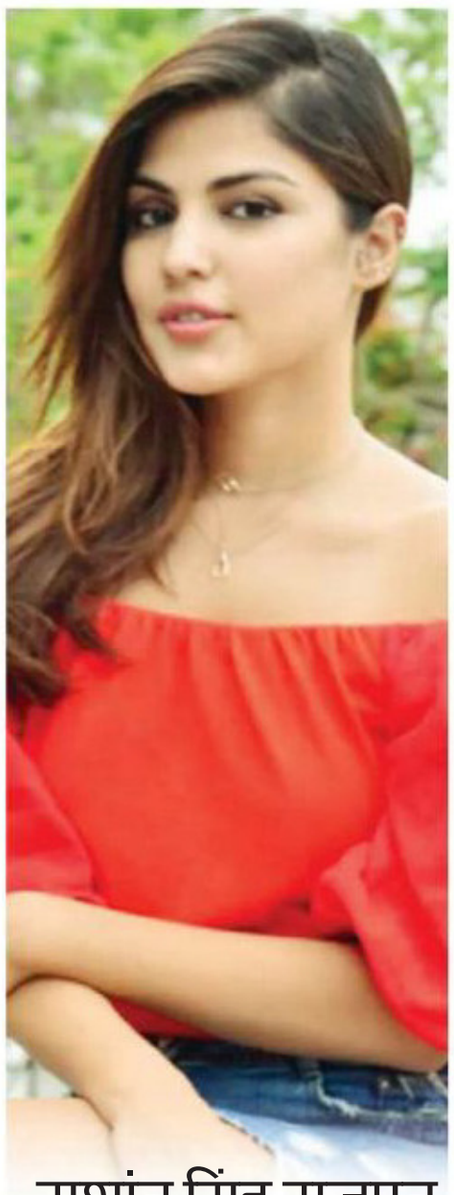

माहिका को आज भी है इस बात का पछतावा

14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 साल पूरा हो गया है। वहीं, इस मौके पर उनके परिवार और फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्रिटीज ने इमोशनल पोस्ट के जरिए सुशांत को याद किया है। इस बीच एक्ट्रेस माहिका शर्मा ने भी उनके साथ बिताए वक्त को याद किया है, उन्होंने बताया है कि सुशांत के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी।

माहिका ने कहा कि सुशांत की मौत की खबर उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वहीं, माहिका ने ये भी बताया है कि उन्हें एक बात का पछतावा भी है।

'मुझे इस बात का पछतावा है'

माहिका शर्मा कई फिल्मों और टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। उन्होंने ई-टाइम्स से बातचीत के दौरान बताया कि 'सुशांत और मैं काफी अच्छे दोस्त थे। जब मैं मुंबई में नई थी, उन्होंने शहर में मुझे सेटल होने में मदद की थी। वो हर तरह से मेरा सपोर्ट करते थे। मेरे दिल में उनके लिए एक खास जगह थी लेकिन मैं ये बयां नहीं कर सकी क्योंकि वो उस वक्त अपनी एक को-स्टार के साथ रिलेशनशिप में थे। मुझे पछतावा है कि मैं उन्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए। मैं उनकी मौत के बारे में सोचकर भी बहुत दुखी हो जाती हूं'।

आत्महत्या पर नहीं है भरोसा

उन्होंने आगे कहा- 'मैं सुशांत के परिवार और चाहने वालों के साथ उन्हें न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वो एक जिंदादिल इंसान थे, वो मस्ती-मजाक करते थे और ये भरोसा करने लायक नहीं है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते थे। लेकिन मुझे भारत के कानून पर भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा'।

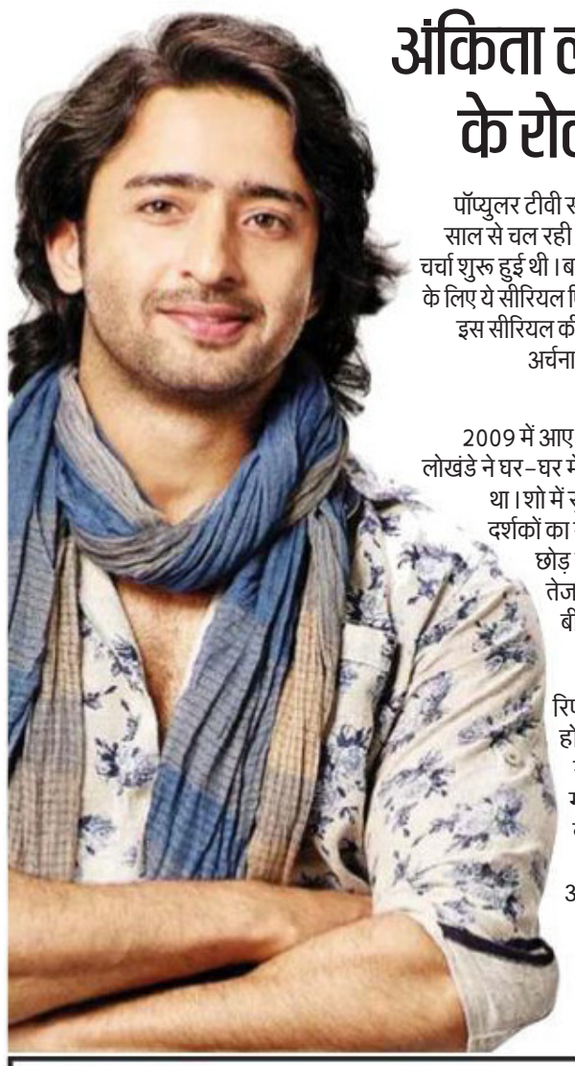

अंकिता लोखंडे के साथ मानव के रोल में होंगे शाहिर शेख

पॉप्युलर टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' का सीक्वल आने की खबरें बीते साल से चल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जून में निधन के बाद इस पर चर्चा शुरू हुई थी। बताया जा रहा था कि एकता कपूर सुशांत को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सीरियल फिर से शुरू करना चाहती हैं। अब रिपोर्ट्स हैं कि फाइनली इस सीरियल की कास्ट तय हो चुकी है। खबरों की मानें तो अंकिता लोखंडे अर्चना के रोल में होंगी और शाहीर शेख मानव के रोल में होंगे।

2011 में सुशांत ने छोड़ा था शो

2009 में आए शो 'पवित्र रिश्ता' से सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे ने घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी। ये अंकिता का डेब्यू सीरियल था। शो में सुशांत मानव और अंकिता अर्चना के रोल में थे और उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला। 2011 में सुशांत सिंह राजपूत ने ये शो छोड़ दिया था। उनके बाद मानव के रोल में 3 साल तक हितेन तेजवानी दिखाई दिए। 2014 में शो ऑफ एयर हो गया था। बीते साल से शो के फिर से शुरू होने की बात चल रही है।

अभी चुनी जानी है बाकी कास्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, पवित्र रिश्ता 20 का कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। एकता कपूर कास्टिंग कर रही हैं। सोर्स के मुताबिक, मानव के रोल के लिए शाहिर शेख को चुना गया है। वहीं अंकिता लोखंडे अर्चना के रोल में दिखाई देंगी। बाकी कास्ट तय की जानी है। हालांकि इस बारे में एकता कपूर या अंकिता लोखंडे की तरफ से कोई ऑफिशल अनाउंसमेंट नहीं है। बताते लें कि बीते साल जब पवित्र रिश्ता 20 की खबरें आई थीं तो सुशांत के फैन्स ने इस पर रिऐक्शंस दिए थे। उनका कहना था कि वे सुशांत की जगह किसी और को नहीं देख सकते।

सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं रिया

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को पहली पुण्यतिथि थी। सुशांत के फैंस और कई सेलेब्स उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती ने उन्हें याद करते हुए एक बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए रिया ने लिखा, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मुझे विश्वास हुआ हो कि आप अब यहां नहीं हैं। कहते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देता है लेकिन आप मेरे समय और मेरे सब कुछ थे। उन्होंने लिखा, मुझे पता है ऊपर से तुम मुझे देख रहे हो.चांद से तुम मुझे अपनी दूरबीन से देख रहे हो और मेरी रक्षा कर रहे हो। मैं हर रोज तुम्हें मुझे लेने आने का इंतजार करती हूं। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती हूं। जब भी मुझे लगता है कि आप यहां नहीं हैं, तो मेरे शरीर में भावनाओं की बाढ़ आ जाती है। तुम्हारे बिना कोई जीवन नहीं है, आप इसका अर्थ अपने साथ ले गए। इस खालीपन को भरा नहीं जा सकता। रिया ने लिखा, मेरे प्यारे सनशाइन बॉय, मैं आपको हर रोज 'मालपुआ' देने का वादा करती हूं और इस दुनिया की सभी क्वांटम फिजिक्स की किताबें पढ़ूंगी- लेकिन मेरे पास वापस आ जाओ. आई मिस यू माय बेस्टफ्रेंड, माय मैन, माय लव। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही रिया चक्रवर्ती लगातार विवादों में छाई हुई हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि रिया ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया है और उनके खाते से पैसे निकाले हैं। वहीं ड्रग्स केस में नाम आने के बाद रिया को जेल भी जाना पड़ा था।

धोनी के बाद इस क्रिकेटर की बायोपिक करना चाहते थे सुशांत

सुशांत सिंह राजपूत को आज दुनिया से बिदा हुए एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर उन्हें उनके प्रशंसक भावुक होकर अपनी-अपनी तरह से याद कर रहे हैं। 14 जनवरी 2020 को सुशांत की मृत्यु हो गई थी। वे अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। जिसने भी यह खबर सुनी उसे यकीन नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की। अभी भी चल रही है। सुशांत को लेकर कई खुलासे हुए थे। जिसमें से एक यह था कि महेंद्र सिंह धोनी पर आधारित बायोपिक 'एमएस धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी' करने के बाद सुशांत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक बनाना चाहते थे। जिसमें वे खुद सौरव गांगुली का किरदार निभाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सौरव से बातचीत की थी। सौरव को 'धोनी' में सुशांत का काम पसंद आया था, लेकिन उन्होंने यह कह कर सुशांत को अपने पर बायोपिक बनाने से रोका कि दर्शक धोनी के रूप में पहले ही सुशांत को पसंद कर चुके हैं इसलिए सौरव के रूप में सुशांत को दर्शक पसंद नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुशांत का ये बायोपिक नहीं बना पाए। सुशांत सिंह राजपूत 12 कैरेक्ट र वाली एक फिल्मय पर काम करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी जैसे किरदारों को एक फिल्म में लाना चाहते थे। लेकिन यह ख्वाहिश भी अधूरी रह गई।

एक साधारण सी प्रेम कहानी का अनुभव करना चाहती हैं रूपल त्यागी

टेलीविजन अभिनेत्री रूपल त्यागी ने कहा है कि वह बचपन से अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी के बारे में सुनकर और सोचकर बड़ी हुई हैं। वह उस दौर में वापस जाना चाहती हैं और सच्ची प्रेम कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हैं। उनके माता-पिता किस तरह से मिले और उनकी डेटिंग कैसे शुरू हुई, इसका जिक्र करते हुए रूपल ने कहा, ''मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ ड्राइविंग कर रहे थे और मेरी मां मेरी मौसी के साथ सड़क के किनारे पैदल जा रही थीं। पापा ने उनकी तरफ देखा और उन्हें उनके बारे में अधिक जानने की तलब हुई।'' वह आगे कहती हैं, ''इसलिए उन्होंने एक ही समय पर उस इलाके का चक्कर लगाना शुरू कर दिया ताकि वह मम्मी को दोबारा देख सके। हालांकि पापा में मम्मी से बात करने की हिम्मत नहीं, तो मम्मी ने ही उनसे जाकर पूछ डाला कि वह रोज उन्हें क्यों देखते हैं और इस तरह से दोनों के बीच प्रेम कहानी की शुरूआत हुई।'' रूपल का मानना है कि आज की पीढ़ी में इस तरह का रोमांस देखने को नहीं मिलता है। वह कहती हैं, ''मैं वाकई में उस दौर में वापस जाना चाहती हूं और इस तरह की किसी प्रेम कहानी का अनुभव करना चाहती हूं, जहां लड़का वाकई में आपको जानना चाहता है, आपको पाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि आज की हमारी पीढ़ी में इस तरह का प्यार कहीं मिसिंग है।'' रूपल इस वक्त टेलीविजन धारावाहिक 'रंजू की बेटियां' में दिखाई दे रही हैं, जिसे दंगल टीवी पर प्रसारित किया जाता है।

आइए फिर से 'सामान्य' के करीब महसूस करें

फिलहाल मॉस्को का दौरा कर रही तापसी पन्नू ने सोमवार को साझा किया कि वह फिर से सामान्य होने के करीब महसूस करना चाहती हैं। तापसी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक नई तस्वीर के साथ अपना तर्क दिया। ''अपने आप को रंगों से घेरने का समय, सड़क के किनारे बैठकर, आकाश की ओर देखते हुए, एक गहरी सांस लें और कहें 'सब ठीक है'! साथ ही हेलो मास्को! चलो फिर से 'सामान्य' के करीब महसूस करते हैं!'' उन्होंने उस तस्वीर के साथ लिखा, जो उसे एक सुरम्य लोकेल में प्रस्तुत कर रही है। उन्हेंने कैप्शन के रूप में लिखा हैशटैग तापसी ट्रैवल्स हैशटैग मास्को हैशटैग रशिया। अभिनेत्री वर्तमान में अपनी आगामी मिस्ट्री थ्रिलर 'हसीन दिलरुबा' की रिलीज का इंतजार कर रही है। फिल्म, जिसमें विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे भी हैं, एक ऐसी महिला के बारे में है, जिसका दिल एक उपन्यास की तरह जीने के लिए तरसता है, लेकिन जो खुद को अपने पति की हत्या में उलझा पाती है। 'हंसी तो फंसी' द्वारा निर्देशित 'हसीन दिलरुबा', निर्देशक विनील मैथ्यू, ओटीटी पर रिलीज होगी।

अश्लील भोजपुरी कंटेंट के खिलाफ रवि किशन ने उठाई आवाज

अभिनेता व गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने केंद्रीय मंत्रियों सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर भोजपुरी फिल्मों और गानों के अश्लील कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता को बैन करने के लिए रवि किशन ने अपनी चिट्ठी में सख्त कानून बनाने की बात लिखी है।

भोजपुरी बोलने वाले लोगों की आबादी करीब 25 करोड़

अपने पत्र में रवि किशन ने कहा है कि देश में भोजपुरी बोलने वाले लोगों की आबादी करीब 25 करोड़ है। रवि कहते हैं, 'ये लोग बेहतर डील के हकदार हैं और भोजपुरी सिनेमा और इसके गानों में अश्लीलता को बंद किया जाना चाहिए।' इसके साथ ही रवि ने कहा कि जो भोजपुरी फिल्में और गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं, उन्हें भी प्रस्तावित कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।

भोजपुरी सिनेमा अश्लीलता का पर्याय बन गया

याद दिला दें कि रवि किशन करीब तीन दशकों से भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए हैं और रीजनल सिनेमा को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रवि किशन कहते हैं, 'मुझे महसूस होता है कि वक्त आ गया है, जब हम अश्लीलता को हटा दें और ये सुनिश्चित करें कि भोजपुरी सिनेमा अपनी क्वालिटी और कंटेंट के लिए जाना जाए। आज के वक्त में भोजपुरी सिनेमा अश्लीलता का पर्याय बन गया है।' इसके साथ ही रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता का युवा पीढ़ी के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गौरतलब है कि भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए रवि किशन ने एक निजी सदस्य विधेयक भी शुरू किया है।

स्नेह राणा ने कराई भारतीय टीम की वापसी, हीथर नाइट ने खेली कप्तानी पारी

नई दिल्ली.ब्रिस्टल में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच का पहला दिन दोनों ही टीमों के लिए मिलाजुला रहा। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 269 रन बना लिए हैं। इंग्लिश टीम की कप्तान हीथर नाइट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 95 रनों की पारी खेली। भारत की ऑफ स्पिन गेंदबाज स्नेह राणा ने आखिरी सेशन में अच्छी गेंदबाजी करके टीम की वापसी कराई।

स्नेह ने तीन विकेट झटके, जबकि दीप्ति शर्मा ने दो विकेट अपने नाम किए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर की चार बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए 21 रन के अंतराल में चार विकेट निकालकर मैच में वापसी कर ली। सलामी बल्लेबाज लॉरेन इनफील्ड हिल ने 63 गेंदों में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 35 रन और टैमी ब्यूमोंट ने 144 गेंदों में छह

चौकों के सहारे 44 रन बनाए। कप्तान हीथर नाइट ने एक छोर संभालकर मजबूती से खेलते हुए 175 गेंदों में नौ चौकों की मदद से 95 रन बनाए। उन्हें ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने पांचवें बल्लेबाज के रूप में एलबीडब्ल्यू किया। हीथर का विकेट 244 के स्कोर पर गिरा।

हीथर ने इससे पहले नताली शिवर के साथ तीसरे विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी की थी। नताली शिवर को भी दीप्ति शर्मा ने एलबीडब्ल्यू किया। शिवर ने 75 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 42 रन बनाए।

स्नेह राणा ने विकेटकीपर एमी एलेन जोंस को मात्र एक रन पर पवेलियन की राह दिखा दिखाई। इंग्लैंड ने अपना चौथा विकेट 236 के स्कोर पर गंवाया। राणा ने जोंस को एलबीडब्ल्यू किया। इंग्लैंड का स्कोर 244 रन पहुंचा ही था कि दीप्ति की शानदार गेंद पर हीथर एलबीडब्ल्यू हो गईं। इंग्लैंड का स्कोर 251 पहुंचा ही था कि स्नेह राणा ने जॉर्जिया एल्विस को दीप्ति शर्मा के हाथों कैच करा दिया। जॉर्जिया ने पांच रन बनाए। इंग्लैंड की अगली दो बल्लेबाजों सोफ़िया डंकली और कैथरीन ब्रंट ने इसके बाद संभलकर खेलते हुए दिन के शेष 10.4 ओवर सुरक्षित निकाल लिए। स्टंप्स के समय सोफिया 47 गेंदों में 12 रन और ब्रंट 30 गेंदों में सात रन बनाकर क्रीज पर डटी थीं।

WTC Final 2021: शेन बॉन्ड ने भारत को चेताया, अगर न्यूजीलैंड ने जीता टॉस तो मुश्किल में पड़ सकती है विराट कोहली की सेना

नई दिल्ली.वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का इंतजार बस खत्म होने को है। भारत और न्यूजीलैंड के साउथैम्पटन में खेले जाने वाले फाइनल मैच पर पूरे विश्व क्रिकेट की निगाहें टिकी हुई हैं। तमाम क्रिकेट फैन्स डब्ल्यूटीसी के पहले विजेता को देखने के लिए उत्सुक हैं। एजिस बाउल के मैदान पर खेले जाने वाले फाइनल में टॉस का रोल भी काफी अहम माना जा रहा है। इसी बीच, पूर्व कीवी तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड का मानना है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल में टॉस जीतने में सफल रहती है तो ऐसे में भारतीय टीम के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती हैं।

बॉन्ड का कहना है कि अगर कीवी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती है तो वह भारतीय टीम को काफी जल्दी समेट देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, अगर न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती है। तो मुझे लगता है कि वह भारत को सस्ते में आउट कर लेगी और यह एक बुरी चीज नहीं है। शेन बॉन्ड ने हालांकि कहा कि अगर न्यूजीलैंड की टीम ऐसा करने में सफल नहीं रहती है तो भारतीय टीम उन पर हावी हो सकती है। उन्होंने कहा, %रिस्क यह है कि अगर भारत को ऑलआउट नहीं कर पाती है, तो इंडिया के पास दो वर्ल्ड क्लास स्पिनर मौजूद हैं जो उनको मैच में बनाए रख सकते हैं। तो टॉस काफी अहम होगा और पहली पारी काफी महत्वपूर्ण रहेगी।

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ने रोहित शर्मा और पंत की तारीफ करते हुए कहा, जैसा कि उन्होंने सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ किया था, यह बहुत मुश्किल विकेट था और वह खुद को ऐसे पेश करते हैं, जैसे वह क्रीज से बाहर आकर बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हैं। वह उस शैली के खिलाड़ी हैं, जो कठिन परिस्थितियों में बहुत गतिशील हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी खेल को दूसरी टीम से दूर ले जा सकते हैं, यहां तक कि अगर न्यूजीलैंड नई गेंद से गेंदबाजी भी करें तो।

EURO CUP: स्विट्जरलैंड को हराकर अंतिम-16 में पहुंचा इटली

रोम. यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 (यूरो कप) में इटली ने अपने शानदार खेल के दम पर स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। मिडफील्डर मैनुअल लोकाटेली ने दो गोल दागे, जबकि सिरो इमोबाइल ने एक गोल किया।

इटली प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। यह उसकी लगातार 10वीं जीत थी। वर्ल्ड कप 2018 में क्वालीफाई करने में नाकाम रहने के बाद इटैलियन टीम ने शानदार वापसी की है। उसके बाद से इटली 29 मैचों में अपराजेय रही है और दसवीं बार विरोधी टीम का सूपड़ा साफ किया है।ग्रुप ए में इटली छह अंक लेकर टॉप पर है। उसने पहले मैच में तुर्की को 3-0 से हराया था। वेल्स चार अंक के साथ दूसरे स्थान पर है जिसने तुर्की को 2-0 से मात दी। स्विटजरलैंड का एक अंक है जबकि तुर्की ने खाता भी नहीं खोला है।

WTC फाइनल के लिए वेंकटेश प्रसाद ने चुना टीम इंडिया का प्लेइंग XI, सिराज, विहारी को नहीं किया शामिल

नई दिल्ली. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के आगाज में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह ऐतिहासिक मैच साउथम्पटन में 18 जून (शुक्रवार) से खेला जाना है। इस मैच के लिए दोनों टीमें अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर चुकी हैं और इन 15 खिलाड़ियों में से ही प्लेइंग XI को लेकर फैसला लिया जाएगा। तमाम पूर्व क्रिकेटर डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग झ्रढ्ढ को लेकर अपना प्रिडिक्शन शेयर कर रहे हैं और इस लिस्ट में अब वेंकटेश प्रसाद भी शामिल हो गए हैं। टीम इंडिया के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने ट्विटर के जरिए अपना प्लेइंग XI शेयर किया है।वेंकटेश प्रसाद ने इस टीम में मोहम्मद सिराज, ऋद्धिमान साहा, हनुमा विहारी और उमेश यादव को प्लेइंग झ्रढ्ढ में शामिल नहीं किया है।

तीन तेज गेंदबाज के तौर पर वेंकटेश प्रसाद ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा को चुना है। वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा, 'मेरा प्लेइंग XI डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी (रोहित, शुभमन, पुजारा, विराट, रहाणे, पंत, जडेजा, अश्विन, शमी, इशांत और बुमराह), उनके पास बॉलिंग और बैटिंग दोनों में गहराई है, पिच चाहे कोई भी हो। यह शानदार मैच होना चाहिए।

अंशुमन गायकवाड की भारतीय टीम को सलाह, हर हाल में मिलनी चाहिए रवींद्र जडेजा को प्लेइंग XI में जगह

नई दिल्ली.टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में बेमिसाल रहा है। जडु ने बल्ले और गेंद दोनों से ही अपनी छाप छोड़ी है। जिसके दम पर उन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम में अपनी जगह को पक्का किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में जडेजा की प्लेइंग इलेवन में जगह को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुछ पूर्व क्रिकेटर्स का मानना है कि भारतीय टीम को जडेजा को बाहर बैठाकर चार प्रमुख तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरना चाहिए। हालांकि, भारत के पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड इस बात से सहमत नहीं है। गायकवाड का मानना है कि जडेजा को हर हाल में प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए।

भारतीय टीम के कोच और पूर्व सिलेक्टर रह चुके अंशुमन गायकवाड ने कहा, रवींद्र जडेजा को किसी भी कीमत पर आप बाहर नहीं बैठा सकते। और वह बाहर बैठे भी क्यों? वह टीम के लिए तीनों ही विभाग में एक बहुत बड़ी एसेस्ट हैं।

वह ट्रिपल-प्लस हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर तीन गेंदबाज इंग्लिश कंडिशंस में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे तो चौथे गेंदबाज उसमें कुछ मदद कर पाएगा। तीन तेज गेंदबाज काफी होंगे। जडेजा का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में बेहद शानदार रहा है। इस साल खेले गए आईपीएल में भी जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से जबरदस्त प्रदर्शन किया था।

गायकवाड ने आगे कहा, आपको एक स्पिनर की जरूरत होगी। अश्विन एक क्लास स्पिनर हैं, लेकिन जडेजा के साथ उनको टीम में खेलना होगा। कितनी ही टीमों के पास लेफ्ट आर्म क्वॉलिटी स्पिनर मौजूद हैं? और यहां आपके पास मौजूद है, सिर्फ एक स्पिनर के तौर पर नहीं बल्कि एक शानदार बल्लेबाज और बतौर बेहतरीन फील्डर। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि उनके हिसाब से डब्ल्यूटीसी फाइनल के पहले दो दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे।

मोहम्मद अहजरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से हटाया गया, नियमों का उल्लंघन करने का लगा आरोप

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। जिसके चलते अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। खबरों के अनुसार अजहरुद्दीन जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान को सितंबर 2019 में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। एपेक्स काउंसिल ने अजहरुद्दीन को एक नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक उनकी मेंबरशिप को भी रद्द कर दिया गया है। टीवी 9% की खबर के मुताबिक, 10 जून को हुई एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में कई मेंबर ने अजहरुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

अजहरुद्दीन पर नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उनको 15 जून को सस्पेंशन का नोटिस भेजा गया। नोटिस के मुताबिक, अगर अजहरुद्दीन एक हफ्ते के भीतर कोई ठोस सबूत पेश नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूर्व भारतीय कप्तान पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खाते से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही यह भी बात सामने आई है कि अजहरुद्दीन दुबई प्राइवेट क्रिकेट क्लब के मेंबर हैं और उन्होंने यह बात एसोसिएशन से छुपाई। अजहरुद्दीन की गिनती भारत के सबसे सफल कप्तानों में की जाती है। अजहर ने भारत के लिए 99 टेस्ट और 334 वनडे खेले हैं।टेस्ट में उन्होंने 45.03 की औसत से 6215 रन बनाए हैं जबकि वनडे में 36.92 की औसत से 9378 रन बनाए हैं। अजहरुद्दीन ने भारत की तरफ से तीन वर्ल्ड कप में कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में भारत ने 14 टेस्ट और 90 वनडे मैचों में जीत दर्ज की है।

WTC Final 2021: टिम साउदी ने की रोहित शर्मा की जमकर तारीफ, कहा- मैच छीनने का रखते हैं दमखम

नई दिल्ली.भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून तक खेला जाना है। दोनों ही टीमों ने इस फाइनल मैच के लिए कमर कस ली है। फाइनल में भारत के बल्लेबाजों और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के बीच में जबरदस्त जंग होने की उम्मीद की जा रही है। साउथैम्पटन में खेले जाने वाले डब्ल्यूटीसी के फाइनल में रोहित शर्मा पर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि, कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि हिटमैन को इंग्लैंड की कंडिशंस में खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने रोहित की जमकर तारीफ की है। साउदी ने कहा कि रोहित के अंदर वह काबिलियत है कि वह विरोधी टीम से अकेले दम पर मैच छीन सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए साउदी ने कहा, रोहित तीनों फॉर्मेट में शानदार खिलाड़ी हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मुझे निजी तौर पर बल्लेबाजी करते हुए देखना पसंद है।

+वह विरोधी से मैच छीन सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी समूह के रूप में मुझे पता है कि पूरा बल्लेबाजी क्रम खतरनाक है। साउथी ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ अनुभवी खिलाड़ियों के नहीं बल्कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों के वीडियो भी देख रही है। साउदी का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए लॉर्ड्स टेस्ट मैच में बेहद शानदार रहा था और उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट अपने नाम किए थे। साउदी ने डब्ल्यूटीसी के फॉर्मट को लेकर बात करते हुए कहा, दो साल के चक्र की शुरुआत में हमें पता था कि फाइनल में सिर्फ एक मुकाबला होगा।श

ायद भविष्य में वे इस पर विचार कर सकते हैं और फिर संभवत-इसमें बदलाव हो सकता है। दो साल पहले इस चक्र की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि चैंपियनशिप जीतने के लिए क्या करने की जरूरत होगी। टेस्ट मैचों को दो साल के चक्र के साथ संदर्भ देना शानदार है। अगले चक्र के लिए पहले ही बदलाव हो रहे हैं। इसलिए यह बदलती हुई चीज है।% न्यूजीलैंड के लिए 78 टेस्ट में 309 विकेट चटकाने वाले साउथी ने कहा कि उनकी टीम ने शुक्रवार से यहां भारत के खिलाफ शुरू हो रहे डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए अच्छी तैयारी की है।

ईशांत शर्मा या मोहम्मद सिराज? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कुछ ऐसी हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग XI

नई दिल्ली .वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को लेकर चल रहा इतंजार अब बस खत्म होने को है। डब्ल्यूटीसी का पहला खिताब अपने नाम करने के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम साउथैम्पटन के एजिस बाउल मैदान पर भिड़ेंगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली के सामने प्लेइंग इलेवन को लेकर काफी कशमाश है। टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर लगभग कंफर्म नजर आ रहा है, लेकिन गेंदबाजी अटैक को लेकर विराट को काफी विचार करना होगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के मूड में है, पर ईशांत शर्मा के पास मौजूद अनुभव को भी नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है।

टॉप ऑर्डर कंफर्म

15 सदस्यीय टीम का ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि रोहित शर्मा के साथ फाइनल मुकाबले में शुभमन गिल पारी का आगाज करेंगे। इंग्लैंड की कंडिशंस में ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी जैसे गेंदबाजों से पार पाने के लिए रोहित-शुभमन को बहुत चतुराई से खेलना होगा। तीन नंबर की पोजिशन पर चेतेश्वर पुजारा खेलते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम को अगर डब्ल्यूटीसी के खिताब पर कब्जा करने है तो पुजारा को न्यूजीलैंड के सामने दीवार बनकर खड़े रहना होगा। पुजारा की हालिया फॉर्म अच्छी रही है और काउंटी क्रिकेट का अनुभव भी पुजारा के काम आ सकता है।

मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे कप्तान और उपकप्तान

भारत के मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के कंधों पर होगी। इंग्लैंड के पिछले दौरे पर कोहली का बल्ला जमकर बोला था। वहीं, रहाणे को भी बड़े मैच का प्लेयर माना जाता है और इस बात को वह एकबार फिर साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोहली नंबर चार की पोजिशन पर खेलते हुए दिखाई देंगे, जबकि रहाणे कप्तान के बाद नंबर पांच पर उतरेंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर सबकी निगाहें रहने वाली है। पंत बैटिंग ऑर्डर में नंबर छह पर खेलते हुए नजर आएंगे।

गेंदबाजी अटैक को लेकर है माथापच्च

साल 2019 के बाद यह पहला मौका है जब ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की तिकड़ी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध है। जसप्रीत बुमराह और शमी का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन, खबरों की मानें तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यादगार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहती है। सिराज को फाइनल में उतारने के लिए कोहली को ईशांत को बाहर बैठाना होगा, लेकिन इस तेज गेंदबाज का 100 से ज्यादा टेस्ट मैचों का अनुभव भी भारत के काम आ सकता है। स्पिन विभाग की बात करें तो रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का खेलना तय है। अश्विन और जडेजा गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं।

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा/मोहम्मद सिराज ।